वर्ष– 14 //अंक–02//अगस्त// 2025
ISSN 2454–5805

आम आदमी पत्रिका

एक आम इंसान की सोच

RNI NO.: CHHHIN/2013/50684

औद्योगिक निवेश का गढ़ बनेगा हमारा राज्य

सीएम हाउस में हरेली तिहार परंपरा और प्रगति की अनूठी झलक

पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे की अंतिम कृति "मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ" का हुआ विमोचन

22

जो भी भारत पर आक्रमण करेगा, वह पाताल में भी सुरक्षित नहीं रहेगा: मोदी

33

छत्तीसगढ़ में व्यापार और वाणिज्य को मिलेगी नई गति

36

युवाओं के सपनों को लगेंगे पर, बनेंगे 34 नए नालंदा परिसर

eyes
events
and advertising
CREATIVITY
IS TAKING A SIMPLE THING
AND BRINGING IT TO LIFE
क्षेत्रीय सरस मेला-2024
रायपुर, छत्तीसगढ़
सशक्त समृद्ध संपन्न महतारी
सहकारिता विभाग
EVENTS | EXHIBITIONS | CORPORATE FILMS | VIDEO COMMERCIAL
Mo. : 97555-23831
www.eyesevents.in
Follow us on

आम आदमी पत्रिका
वर्ष–14 //अंक–02// अगस्त//2025

प्रबंध संपादक : उमेश के बंसी
सर्कुलेशन इंचार्ज : प्रकाश बंसी
रिपोर्टर : नेहा श्रीवास्तव
कंटेंट राईटर : प्रशांत पारीक
क्रिएटिव डिजाइनर : जितेन्द्र साहू
मैग्ज़ीन डिज़ाइनर : मयंक पवार
एडमिनिस्ट्रेशन : कुसुम श्रीवास्तव
अकाउंट असिस्टेंट : उत्कर्ष चौधरी
ऑफिस कॉर्डिनेटर : योगेन्द्र बिसेन

प्रधान कार्यालय
54/111, सालासर बालाजी मंदिर के पास,
अग्रसेन धाम के पीछे, वी.आई.पी.रोड, रायपुर (छ.ग.)
फोन : 0771-4044047
ईमेल : khabar@aamaadmi.in
कार्यालय
प्लाट नं.118, कंचन बाग, राजनांदगांव

प्रकाशक
उमेश कुमार बंसी, क्वाटर नंबर 10, एम.एम. रियल स्टेट कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित एवं मुद्रित

विशेष- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गए विचार, लेखकों के अपने है। इसमें संपादक / मुद्रक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संपादक / मुद्रक जिम्मेदार नहीं होगा। इस पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद के लिए सुनवाई क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा।

अनुक्रमणिका

अगस्त 2025

इस अंक में

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में नवा रायपुर को सोलर सिटी बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी एवं राजेश सिंह राणा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के संवेदनशील एवं दूरदर्शी नेतृत्व में क्रेडा द्वारा नवा रायपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए दिए गए प्रस्ताव पर अटल नगर, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एन.आर.डी.ए.) द्वारा अपनी सहमति दे दी गई है। अब आने वाले दिनों में इसके लिए व्यापक कार्ययोजना बनाकर कार्य प्रारंभ करने की तैयारी शुरु होगी। 05

आत्मसमर्पित माओवादियों को मिल रहा नया जीवन 10

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू माओवादी आत्मसमर्पण राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 और बस्तर संभाग के अंदरूनी गांवों के समग्र विकास के लिए विशेष रूप से संचालित 'नियद नेल्ला नार' योजना ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और विश्वास का नया मार्ग प्रशस्त किया है।

उस नदी की कहानी, जिसने धराली को तबाह कर दिया 20

चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है.

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कितना पानी पीना चाहिए 26

किडनी इंसान के शरीर के उन अहम अंगों में से एक है, जिस पर शरीर को स्वस्थ रखने की कई जिम्मेदारियां होती हैं।

पाठशालाओं में जब बजेगी घण्टी, होगी स्कूलों में शिक्षकों की गारंटी 28

टन...टन... टन... टन... घण्टी की यह आवाज अब फिर से स्कूलों में सुनाई देने ही वाली है। ग्रीष्म अवकाश के बाद लम्बे दिनों के अंतराल में क्लास रूम की चहल-पहल में क, ख, ग और ए, बी, सी, डी की शोर भी सुनाई देगी।

एडवेंचर, अध्यात्म का अदभुत संगम कोरबा के अनछुए पर्यटन रत्न 32

अगर आपका गोवा जाने का प्लान है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है. छत्तीसगढ़ में रहकर ही मिनी गोवा का एहसास कर सकते हैं।

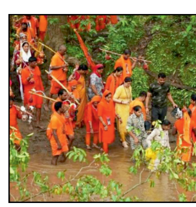

नदी-जंगल और कठिन रास्ते तय कर भोरमदेव मंदिर में किया जलाभिषेक 34

पंडरिया नगर में दिखा जनसैलाब, हुआ भगवामय वातावरण डोंगरिया महादेव में जलाभिषेक के बाद जब यात्रा पंडरिया नगर पहुंची, तो वहां भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा।

नेक इरादे से नैया होगी पार

उमेश के बंसी
(प्रबंध संपादक)

वो कहते है न कि नेक इरादे हो तो निश्चित तौर पर हर तरफ आपके नाम की चर्चा भी खूब होती है। कुछ इस तरह से नेक इरादे सत्ता के साथ भी नेताओं को होने चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से यहां बस्तर में नक्सलियों की वजह से खौफ बहुत ही था, एक वक्त इसकी चर्चा दूर-दूर तक होती थी, लेकिन आज की परिस्थिति में बदलाव जरूर आया है। क्योंकि अब लोग यहां पर्यटन को इंजॉय कर रहे हैं और इतना ही नहीं, यहां एक्सप्लोर करने में भी बाहरी पर्यटकों को भी आनंद आ रहा है। बस्तर में कुछ योजनाओं की वजह से बदलाव नजर आने लगा है। सरकार का नेक इरादा था, तभी नियद निल्लानार योजना ने सबकुछ बदलाव की ओर लाना शुरू कर दिया। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे मूलभूत सुविधाएं। अब धीरे-धीरे दूरस्थ गांवों तक पहुंच रही है।

इन बदलावों के पीछे सरकार की मंशा रही है कि जो सालों से सुविधाओं से वंचित रहे है। उन्हें उनका हक और अधिकार भी दिलाया जाना चाहिए। इसी मासिकता के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। हालांकि कुछ रूकावटें माओवादी घटनाओं की वजह से होती है, लेकिन जवानों के हौंसले कभी कम नहीं होते है और विकास और विश्वास का गठजोड़ तैयार हो रहा है। इसलिए नए-नए आयाम दिखने लगे है, जो लोग कभी रायपुर तक नहीं पहुंच पाते थे, वे अब रायपुर का नजारा देखकर आनंदित हो रहे है। सरकार का प्रयास है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं, जंगल के भीतर में रहने वालों को दिया जाएं। इसी विचार के साथ प्रस्ताव बनाया जा रहा है और उसे अमलीजामा पहनाया जा रहा है। कुछ क्षेत्र जहां पर्यटक जाने से घबराते थे, सुविधाओं का अभाव होता था, वहां अब स्थिति, परिस्थिति बदल रही है। अब सभी तरह की सुविधाएं भी हो रही है। खास यह है कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी खूब मिल रहा है। रोजगार के नए-नए आयाम खुल रहे है। यह सब संभव हो पाया है सरकार के नेक इरादों से। माओवादियों को न्यूट्रालाइज करने का काम भी तेजी से चल रहा है। क्योंकि बस्तर में शांति का वातावरण बना रहे है और लोग बिना किसी भय के वहां भ्रमण कर रहे। सुरक्षा कैंपों का दायरा भी हर क्षेत्रों में बढ़ा है। फोर्स का मूवमेंट अब हर तरफ दिखाई पड़ रहा है। इससे माओवादियों की जड़ें अब खत्म होने जा रही है। 2026 तक लक्ष्य हैं, वह अब निकट भी आ रहा है और माओवादियों की काली छाया भी अब हटने वाली है। बस्तर में नजर आएगा, सुकून, शांति और निर्भय....।

नवा रायपुर बनेगा राज्य का पहला सोलर सिटी

सभी शासकीय भवन होगें सौर ऊर्जा से रोशन

- **सोलर सिटी योजना के तहत् 10 मेगावाट का सोलर पॉवर प्लांट लगाने का लक्ष्य।**
- **सलाना 160 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन।**
- **बिजली बिल में लगभग 14.50 करोड़ रूपए की बचत।**

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में नवा रायपुर को सोलर सिटी बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी एवं राजेश सिंह राणा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के संवेदनशील एवं दूरदर्शी नेतृत्व में क्रेडा द्वारा नवा रायपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए दिए गए प्रस्ताव पर अटल नगर, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एन.आर.डी.ए.) द्वारा अपनी सहमति दे दी गई है। अब आने वाले दिनों में इसके लिए व्यापक कार्ययोजना बनाकर कार्य प्रारंभ करने की तैयारी शुरू होगीं।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट क्षमता के ऊर्जा उत्पादन अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र परियोजना प्रचलित है। ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्रों की स्थापना हेतु छायामुक्त स्थल तथा भवन के अनुबंध भार के आधार पर क्षमता निर्धारित की जाती है तथा संयंत्र स्थापित कर विद्युत् को नेट मीटरिंग प्रणाली के तहत् ग्रिड में प्रवाहित किया जाता है। वर्तमान में राज्य में 01 से 500 किलोवाट क्षमता तक के ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र को नेट मीटरिंग प्रणाली के तहत् स्थापित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) ने नवा रायपुर को सोलर सिटी बनाने के लिए राज्य सरकार से 65 करोड़ रूपए की राशि मांग की गई है। इसके तहत मंत्रालय एवं शासकीय विभागों के मुख्यालय भवन तथा अन्य कार्यालय भवन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और रेलवे स्टेशन जैसे बड़े परिसर, तथा स्ट्रीट लाईट सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र से रोशन होंगे। पहले चरण में 10 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र लगाए जाएंगे। उक्त संयंत्र से उत्पादित विद्युत को सीधे ग्रिड में प्रवाहित किया जाएगा। इससे हर साल करीब 160 लाख यूनिट बिजली उत्पादन अनुमानित है। जिसमें लगभग 14.50 करोड़ रूपए बिजली बिल में वार्षिक बचत होने का अनुमान है तथा सोलर पॉवर प्लांट के जीवन काल तक 350 से 400 करोड़ रूपए की बचत होना अनुमानित है। पूर्व में क्रेडा द्वारा मंत्रालय, इंद्रावती भवन, व्यापमं, पुलिस मुख्यालय सहित कई सरकारी भवनों में 2.5 मेगावाट का संयंत्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

सीएम हाउस में हरेली तिहार
परंपरा और प्रगति की अनूठी झलक

● सरगुजिहा कला पर केंद्रित सजावट में बस्तर और मैदानी छत्तीसगढ़ की भी सुंदर झलक

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक अस्मिता और कृषि परंपराओं का प्रतीक हरेली तिहार इस वर्ष मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निवास परिसर में अत्यंत हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्य की समृद्ध विरासत, पारंपरिक कृषि यंत्रों, लोक परिधानों, खानपान और आधुनिक कृषि तकनीकों का समन्वय एक अद्भुत नजारे के रूप में सामने आया। कार्यक्रम स्थल को पारंपरिक छत्तीसगढ़ी रंग-रूप में सजाया गया था, जहां ग्रामीण परिधान पहने अतिथि, कलाकार और आमजन लोक संस्कृति में रमे हुए नजर आए।

हरेली उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री निवास में परम्परागत और आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदर्शनी स्थल का भ्रमण कर विभिन्न पारंपरिक यंत्रों और वस्तुओं का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में काठा, खुमरी, झांपी, कांसी की डोरी और तुतारी जैसे ऐतिहासिक कृषि उपकरणों को प्रदर्शित किया गया। कृषि विभाग द्वारा आयोजित आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी, जिसमें नांगर, कुदाली, फावड़ा, रोटावेटर, बीज ड्रिल, पावर टिलर और स्प्रेयर जैसे यंत्रों का प्रदर्शन किया गया। 'काठा' वह परंपरागत मापक है जिससे पुराने समय में धान तौला जाता था, 'खुमरी' बांस और कौड़ियों से बनी छांव प्रदान करने वाली टोपी है, 'झांपी' शादी-ब्याह में उपयोग होने वाली वस्तुएं रखने की बांस से बनी पेटीय 'कांसी की डोरी' खाट बुनने में काम आती है और 'तुतारी' पशुओं को संभालने में उपयोग होती है।

मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि हरेली तिहार केवल पर्व नहीं, बल्कि यह हमारे कृषि जीवन, पशुधन और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी किसानों, युवाओं और आमजनों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। मुख्यमंत्री ने इन उपकरणों की जानकारी लेकर कृषि तकनीकी प्रगति की सराहना की और कहा कि छत्तीसगढ़ की खेती परंपरा और तकनीक के समन्वय से और भी अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनेगी। किसानों को नई तकनीकों की

जानकारी देकर हम राज्य की कृषि उत्पादकता को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम नागरिक, किसान, छात्र और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस आयोजन ने छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति और कृषि नवाचार के अद्वितीय संगम को सजीव रूप में प्रस्तुत किया, जो राज्य की समृद्ध परंपरा और विकासशील सोच का प्रतीक है।

छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के स्वादों से सजी रही पारंपरिक थाली

छत्तीसगढ़ की धरती पर जब भी कोई त्योहार आता है, तो वह केवल धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव भर नहीं होता, बल्कि वह जीवनशैली, परंपरा, स्वाद और सामाजिक सौहार्द का पर्व बन जाता है। इसी श्रृंखला में प्रदेश के प्रमुख कृषि पर्व हरेली तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निवास में पारंपरिक स्वादिष्ट छत्तीसगढ़ी व्यंजनों ने सभी अतिथियों का मन मोह लिया। प्रदेश की अतुलनीय पाक परंपरा को जीवंत करते हुए यहां आगंतुकों के स्वागत के लिए विशेष रूप से ठेठरी, खुरमी, पिड़िया, अनरसा, खाजा, करी लड्डू, मुठिया, गुलगुला भजिया, चीला-फरा, बरा और चौसेला जैसे दर्जनों पारंपरिक व्यंजनों की व्यवस्था की गई थी।

बांस की सूप, पिटारी और दोना-पत्तल में परोसे गए इन व्यंजनों ने न केवल स्वाद, बल्कि प्रस्तुतीकरण में भी लोकजीवन की आत्मा को उजागर किया। अतिथियों ने गर्मागर्म पकवानों का स्वाद लेते हुए राज्य की पारंपरिक पाककला की मुक्तकंठ से सराहना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वयं भी इन व्यंजनों का स्वाद चखा और कहा की हरेली तिहार केवल खेती-किसानी का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारी लोक संस्कृति, हमारी परंपरा और आत्मीयता की अभिव्यक्ति है। इन पारंपरिक व्यंजनों में हमारी माताओं-बहनों की मेहनत, सादगी और स्वाद की समृद्ध परंपरा छिपी है, जो हमारी असली पहचान है। यह आयोजन न केवल हरेली पर्व की महत्ता को दर्शाता है, बल्कि यह प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ की आत्मा उसकी मिट्टी, उसके स्वाद और उसकी परंपराओं में रची-बसी है।

इस अवसर पर परिसर का हर कोना छत्तीसगढ़ी संस्कृति की सौंधी खुशबू से सराबोर था। कहीं ढोल-मंजीरों की थाप पर लोक नृत्य होते दिखे तो कहीं व्यंजनों की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींचती रही। परंपरागत वेशभूषा में सजे ग्रामीण कलाकारों और सांस्कृतिक प्रस्तुति ने पूरे माहौल को जीवंत और आत्मीय बना दिया। कार्यक्रम में शामिल हुए वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कलाकारों और आमजनों ने इस आयोजन को एक स्मरणीय सांस्कृतिक अनुभव बताया।

सरगुजिहा कला पर केंद्रित सजावट में बस्तर और मैदानी छत्तीसगढ़ की भी सुंदर झलक

छत्तीसगढ़ की परंपरा में "हरेली" मानव और प्रकृति के जुड़ाव को नमन करने का उत्सव है। हरेली आती है तो छत्तीसगढ़ के खेत-खलिहान, गाँव-शहर, हल और बैल, बच्चे-युवा-महिलाएँ सभी इस पर्व के हर्षोल्लास से भर जाते हैं। जिस हरेली पर्व से छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत होती है, उसके स्वागत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास के द्वार भी सज गए हैं। पूरा मुख्यमंत्री निवास श्रावण अमावस्या को मनाये जाने वाले हरेली पर्व की सुग्घर परंपरा के रंग में रंग गया है। हरेली पर मुख्यमंत्री निवास की सजावट के तीन प्रमुख हिस्से हैं। प्रवेश द्वार, मध्य तोरण द्वार और मुख्य मंडप। प्रवेश द्वार में बस्तर के मेटल आर्ट की झलक है। इस द्वार पर लोगों के स्वागत में छत्तीसगढ़ का पारम्परिक वाद्य तुरही के मध्य में भगवान गणेश की प्रतिकृति है और मेटल आर्ट का

घोड़ा भी उकेरा गया है।

प्रवेश द्वार के बाद मध्य में तोरण द्वार है जिसे पारम्परिक टोकनी से सजाया गया है। साथ ही रंग-बिरंगी छोटी झंडियाँ तोरण के रूप में शोभा बढ़ा रही हैं। इस हिस्से में नीम और आम पत्तों की झालर को हरेली की परम्परा के प्रतीक के रूप में लगाया गया है। पूरी सजावट का मुख्य आकर्षण वे छोटी-छोटी रंग-बिरंगी गेड़ियां हैं, जिनका सुंदर स्वरूप यहां से मुख्य मंडप तक हर जगह दिखता है।

मुख्य मंडप द्वार को सरगुजा की कला के रंगों से आकर्षक बनाया गया है। इस द्वार की छत को पैरा से छाया गया है और सरगुजिहा भित्ति कला का के मनमोहक चित्र बनाये गए हैं। कई रंगों से सजा बैलगाड़ी का चक्का भी इस द्वार की रौनक बढ़ा रहा है।

मुख्य कार्यक्रम मंडप के बाएँ हिस्से में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश का पारम्परिक घर बना है। इस घर के आहते को मैदानी छत्तीसगढ़ की चित्रकला से सजाया गया है। घर के आँगन में तुलसी चौरा और गौशाला है, जहाँ हल, कुदाल, रापा, गैती, टंगिया, सब्बल जैसे पारम्परिक कृषि यंत्र के साथ ही गोबर के उपले रखे हैं। इस ग्रामीण घर की दीवारों को सरगुजा की रजवार पेंटिंग के सुंदर चित्रों से सजाया गया है।

कार्यक्रम मंडप में कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण है। खास बात यह है कि इस प्रदर्शनी में पारम्परिक और आधुनिक कृषि यंत्रों को एक साथ प्रदर्शित किया गया है। पैडी सीडर, जुड़ा, बियासी हल, तेंदुआ हल और ट्रैक्टर जैसे यंत्र प्रदर्शित हैं।

मंडप में एक ओर पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के जलपान का हिस्सा है तो वहीं सावन का झूला भी सावन के फुहारों भरे मौसम के आंनद को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ का पारम्परिक रहचुली झूला भी आकर्षण का केंद्र है।

संस्कृति की छटा बिखेरते पारम्परिक नृत्यः

हरेली के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में गेड़ी नृत्य और राउत नाचा जैसे पारम्परिक लोक नृत्य की छटा भी मनमोहक धुनों के साथ बिखर रही है। गेड़ी नृत्य के लिए बिलासपुर से दल आमंत्रित किया गया है। गेड़ी नृत्य के दल ने वेशभूषा में परसन वस्त्र के साथ सिर पर सीकबंद मयूर पंख का मुकुट, कौड़ी व चिनीमिट्टी से बनी माला और कौड़ी जड़ित जैकेट पहन रखा है। यह दल माँदर, झाँझ, झुमका, खँजरी, हारमोनियम और बाँसुरी की मधुर धुन में अपनी प्रस्तुति दे रही है। गौरतलब है कि गेड़ी नृत्य की शुरुआत हरेली के दिन से होती है।

हरेली के मौके पर मुख्यमंत्री निवास में गड़बेड़ा (पिथौरा) से राउत नाचा के लिए 50 लोगों का दल पहुँचा है। इस दल में पुरुषों ने जहाँ धोती-कुर्ता के साथ सिर पर कलगी लगी पगड़ी, कौड़ी जड़ित बाजूबंद और पेटी के साथ पैरों में घुँघरू पहना है तो महिलाएँ

भी पारम्परिक श्रृंगारी करके पहुँची हैं। इन दोनों ही दलों के सदस्यों ने बताया कि उन्हें इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास पहुँचने का बेसब्री से इंतजार रहता है।

छत्तीसगढ़ी परंपराओं की झलक

छत्तीसगढ़ी लोकजीवन की खुशबू लिए हरेली तिहार का पारंपरिक उत्सव आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निवास में विधिवत रूप से आरंभ हुआ। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ प्रत्येक अवसर और कार्य के लिए विशेष प्रकार के पारंपरिक उपकरणों एवं वस्तुओं का उपयोग होता आया है। हरेली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में ऐसे ही पारंपरिक कृषि यंत्रों एवं परिधानों की झलक देखने को मिली, जो छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर हैं।

काठा

सबसे बाईं ओर दो गोलनुमा लकड़ी की संरचनाएँ रखी गई थीं, जिन्हें 'काठा' कहा जाता है। पुराने समय में जब गाँवों में धान तौलने के लिए काँटा-बाँट प्रचलन में नहीं था, तब काठा से ही धान मापा जाता था। सामान्यत: एक काठा में लगभग चार किलो धान आता है। काठा से ही धान नाप कर मजदूरी के रूप में भुगतान किया जाता था।

खुमरी

सिर को धूप और वर्षा से बचाने हेतु बांस की पतली खपच्चियों से बनी, गुलाबी रंग में रंगी और कौड़ियों से सजी एक घेरेदार संरचना 'खुमरी' कहलाती है। यह प्राय: गाय चराने वाले चरवाहों द्वारा सिर पर धारण की जाती है। पूर्वकाल में चरवाहे अपने साथ 'कमरा' (रेनकोट) और खुमरी लेकर पशु चराने निकलते थे। 'कमरा' जूट के रेशे से बना एक मोटा ब्लैंकेट जैसा वस्त्र होता था, जो वर्षा से बचाव के लिए प्रयुक्त होता था।

कांसी की डोरी

यह डोरी 'कांसी' नामक पौधे के तने से बनाई जाती है। पहले इसे चारपाई या खटिया बुनने के लिए 'निवार' के रूप में प्रयोग किया जाता था। डोरी बनाने की प्रक्रिया को 'डोरी आंटना' कहा जाता है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में खेतों की मेड़ों पर कांसी पौधे उग आते हैं, जिनके तनों को काटकर डोरी बनाई जाती है। यह डोरी वर्षों तक चलने वाली मजबूत बुनाई के लिए उपयोगी होती है।

झांपी

ढक्कन युक्त, लकड़ी की गोलनुमा बड़ी संरचना 'झांपी' कहलाती है। यह प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ में बैग या पेटी के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होती थी। विशेष रूप से विवाह समारोहों में बारात के दौरान दूल्हे के वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, पकवान आदि रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यह बांस की लकड़ी से निर्मित एक मजबूत संरचना होती है, जो कई वर्षों तक सुरक्षित बनी रहती है।

कलारी

बांस के डंडे के छोर पर लोहे का नुकीला हुक लगाकर 'कलारी' तैयार की जाती है। इसका उपयोग धान मिंजाई के समय धान को उलटने-पलटने के लिए किया जाता है।

आत्मसमर्पित माओवादियों को मिल रहा नया जीवन

युवाओं और महिलाओं की बदली जिंदगी

राज्य सरकार की माओवादी आत्मसमर्पण राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 ला रही रंग

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू माओवादी आत्मसमर्पण राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 और बस्तर संभाग के अंदरूनी गांवों के समग्र विकास के लिए विशेष रूप से संचालित 'नियद नेल्ला नार' योजना ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और विश्वास का नया मार्ग प्रशस्त किया है। इस योजना के कन्वर्जेंस के माध्यम से जिला प्रशासन सुकमा द्वारा आत्मसमर्पित माओवादियों को कौशल प्रशिक्षण, पुनर्वास एवं स्वरोजगार से जोड़कर समाज की मुख्यधारा में सफलतापूर्वक जोड़ा जा रहा है।

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन में चल रहे इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाइवलीहुड कॉलेज एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न ट्रेड में निरूशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आत्मसमर्पित युवा और महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी होकर समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें।

पुनर्वास केंद्र बना नई राह की शुरुआत

कोंटा विकासखंड की अनीता सोड़ी जैसी आत्मसमर्पित महिलाओं के जीवन में यह योजना नई दिशा लेकर आई है। अनीता बताती हैं कि पुनर्वास केंद्र ने हमें यह एहसास कराया कि शांति और सम्मान से भी जीवन जीया जा सकता है। सिलाई, कृषि समेत अन्य आजीविका प्रशिक्षणों ने हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया है। अब मैं स्वयं का सिलाई कार्य प्रारंभ कर परिवार को बेहतर भविष्य देना चाहती हूं। अनीता के साथ वेट्टी कन्नी, हड़मे माड़वी, कड़ती विज्जे समेत 6 आत्मसमर्पित महिलाएं लाइवलीहुड कॉलेज सुकमा में चल रहे एक माह के सिलाई प्रशिक्षण में हिस्सा ले रही हैं। 'सक्षम योजना' के अंतर्गत उन्हें 40 हजार से 2 लाख रुपये तक का ऋण 3: ब्याज दर पर उपलब्ध

कराया जाएगा तथा निःशुल्क सिलाई मशीन एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।

सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल

लाइवलीहुड कॉलेज में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 किशोरी बालिकाएं एवं महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। इन्हें ब्लाउज, ड्रेस, स्कूल यूनिफॉर्म एवं शर्ट-पैंट की सिलाई की ट्रेंनिग दी जा रही है। साथ ही नोनी सुरक्षा योजना, महतारी वंदन योजना, सक्षम योजना, एवं महिला ऋण योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल भी की जा रही है, जिससे महिला सशक्तिकरण को नई गति मिल रही है। नियद नेल्ला नार योजना से बस्तर में विकास और विश्वास की बहार बह रही है। अब तक 79 आत्मसमर्पित माओवादियों को सिलाई, कृषि-नर्सरी, वाहन-चालन, राजमिस्त्री एवं उद्यमिता जैसे ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आगामी सप्ताह से 30 युवा राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए आरसेटी में प्रशिक्षण लेंगे। पुनर्वास केंद्र सुकमा में वर्तमान में 42 प्रशिक्षणार्थी (21 महिलाएं) निवासरत हैं जिन्हें क्रमशः कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है।

स्वरोजगार की राह दिखाई

योजना के कन्वर्जेंस से युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास, सक्षम, पीएम स्वनिधि, स्टार्टअप, कृषि उद्यमिता और महिला ऋण योजनाओं से जोड़कर स्वरोजगार की राह दिखाई जा रही है जो बस्तर के अंदरूनी गांवों में रोजगार, सम्मान तथा विकास के नए युग का सूत्रपात कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की दूरदर्शी नीति और 'नियद नेल्ला नार' योजना ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब सरकार संवेदना, अवसर और कौशल के साथ लोगों तक पहुँचती है तो बदलाव सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि सुनिश्चित होता है। बस्तर की यह परिवर्तन यात्रा आने वाले समय में शांति, विकास और समृद्धि की स्थायी नींव तैयार करेगी।

औद्योगिक निवेश का गढ़ बनेगा हमारा राज्य

◦ 6 लाख करोड़ से ज्यादा के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव

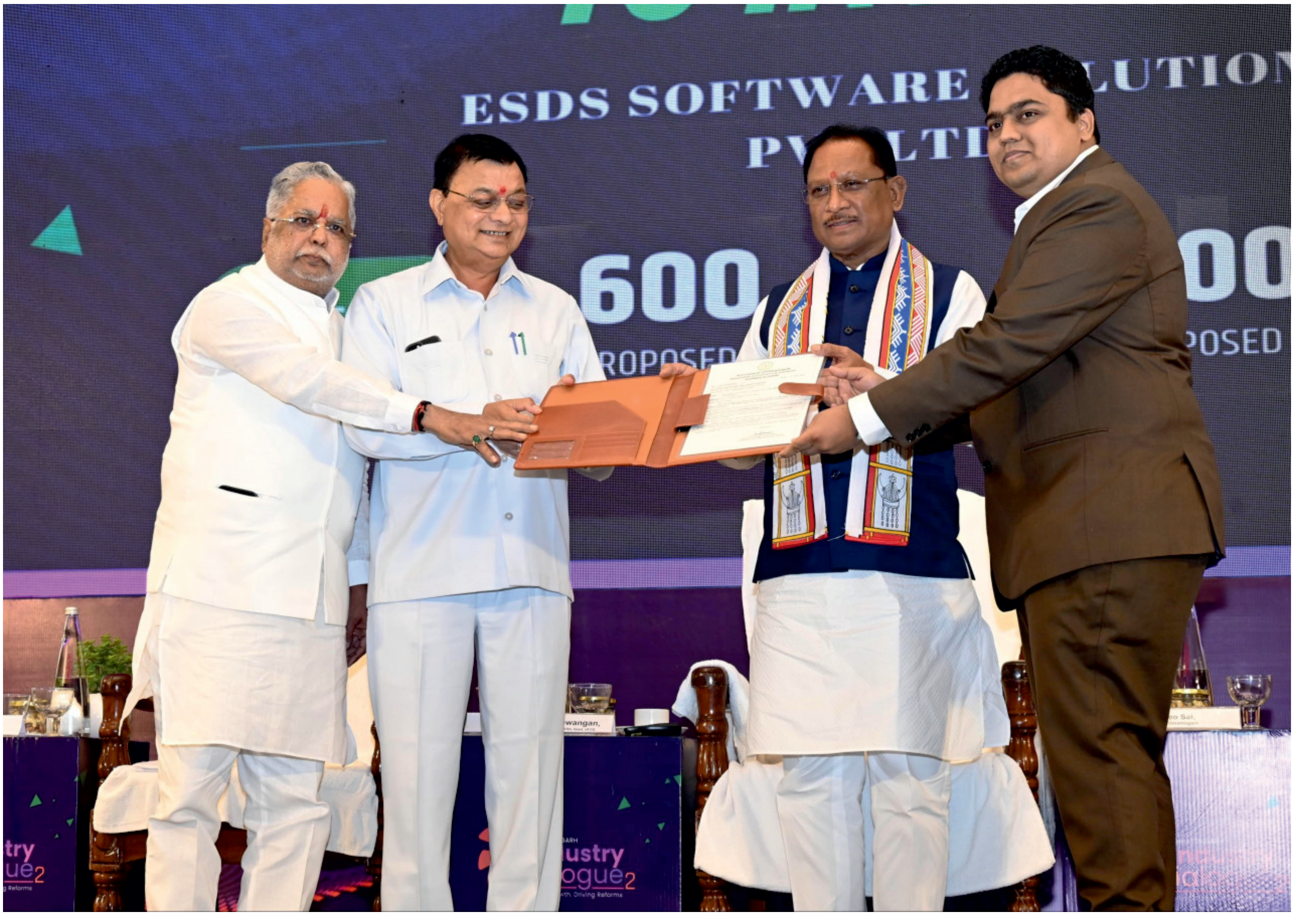

छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। यह नीति छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति देश की कनेक्टिविटी का केंद्र बिंदु है। यह नीति लॉजिस्टिक सेक्टर और ई-कॉमर्स में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करेगी, निर्यात अधोसंरचना को मजबूत करेगी और सस्ती भंडारण सुविधाओं का विस्तार करेगी। लॉजिस्टिक नीति से राज्य में ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा, उद्योग, व्यापार और किसानों को आधुनिक, सस्ती भंडारण और वितरण सुविधा प्राप्त होगी, लॉजिस्टिक लागत में कमी के माध्यम से व्यापार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जन विश्वास विधेयक से व्यवसाय और नागरिक जीवन में अनावश्यक जटिलताएं दूर होंगी। कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण करने से व्यवसायियों को बेवजह न्यायालयीन प्रकरणों में फंसने से राहत मिलेगी और न्यायिक खर्च में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से व्यापार व जीवनयापन में सहजता सुनिश्चित की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास है कि निवेशकों, उद्योगपतियों और नागरिकों के लिए ऐसा परिवेश बने जिसमें न्यूनतम बाधाएं हों और विकास के हर क्षेत्र में अधिकतम संभावनाएं खुलें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में 350 से अधिक संरचनात्मक सुधार

योजनाओं से इस दिशा में सार्थक कार्य होगा।

'अंजोर विजन' दस्तावेज में मैन्यु-फैक्चरिंग सेक्टर को प्रमुखता

मुख्यमंत्री ने उपस्थित उद्यमियों को बताया कि विकसित भारत/2047 के लक्ष्य के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की परिकल्पना पर आधारित अंजोर विजन डाक्यूमेंट तैयार कर लिया गया है। इस दस्तावेज में चरणबद्ध रूप से विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। उन्होंने बताया कि इस विजन दस्तावेज में सर्वाधिक फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की कोर-इंडस्ट्री जैसे स्टील एवं पावर-को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

लागू किए गए हैं, जिनसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस में अभूतपूर्व सुधार हुआ। प्रदेश में निवेश का वातावरण इतना सशक्त हुआ कि सिर्फ छह महीनों में साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक इतिहास में रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में आयोजित इंवेस्टर्स समिट से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने भारी उत्साह दिखाया। दिल्ली समिट में 15,184 करोड़ रूपए, मुंबई में 6,000 करोड़ रूपए और बेंगलुरु में ऊर्जा क्षेत्र में वृहद निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025 में 1,63,749 करोड़ रूपए का निवेश आकर्षित किया, जो भारत के कुल निवेश का 3.71 प्रतिशत है।

नई औद्योगिक नीति में स्टील सेक्टर को विशेष रूप से प्रोत्साहन

साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में स्टील सेक्टर को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया है। यदि कोई उद्यमी ग्रीन स्टील का उत्पादन कर रहा हो, तो उसे विशेष अनुदान देने का प्रावधान भी छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्टील हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उनके नेतृत्व में देश में स्टील उत्पादन 100 मिलियन टन से बढ़कर 200 मिलियन टन हो गया है, और वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 300 मिलियन टन तक पहुँचाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में भी स्टील की वर्तमान उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन से बढ़ाकर 45 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।

छतीसगढ़ःखनिज संसाधनों से समृद्ध, औद्योगिक संभावनाओं से परिपूर्ण राज्य

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपने भरपूर खनिज संसाधनों के कारण समृद्ध है। इनके उचित दोहन से यहाँ औद्योगिक संभावनाओं में अत्यधिक विस्तार संभव है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अधिकतम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और राज्य सरकार की स्थानीय लोगों को रोजगार देने हेतु अनुदान

लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधोसंरचना सहित सभी तैयारियाँ पूर्ण

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधोसंरचना सहित सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। राज्य में रेलवे अधोसंरचना को सशक्त किया गया है। तेजी से रेल नेटवर्क और उससे संबंधित अधोसंरचना का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे स्टील सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 47 हजार करोड़ रुपये की लागत से रेलवे के विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर कार्य हो रहा है। अब रावघाट से जगदलपुर रेलमार्ग पर भी कार्य आरंभ होगा। किरंदुल से तेलंगाना के कोठागुडेम तक नई रेललाइन बिछाई जाएगी, जिसमें 138 किलोमीटर का हिस्सा बस्तर से गुजरेगा। रायगढ़ के खरसिया से राजनांदगांव के परमालकसा तक नया रेल नेटवर्क बनाकर कई प्रमुख औद्योगिक केंद्रों तक कच्चे माल की आपूर्ति एवं तैयार माल की ढुलाई की प्रक्रिया आसान की जाएगी, जिससे उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी।

इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 350 से अधिक सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और इज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया को लागू किया गया है। साथ ही 350 से अधिक नीतिगत सुधार किए गए हैं, जिनका सीधा लाभ स्टील सेक्टर में किए गए निवेशकों को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीन एनर्जी को अपनाने वाले औद्योगिक संस्थानों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। श्री साय ने राज्य में ग्रीन स्टील उत्पादन हेतु हाइड्रोजन जैसी उन्नत तकनीकों के उपयोग पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ माह पूर्व आयोजित एनर्जी समिट में छत्तीसगढ़ में लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 57 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा (सोलर एनर्जी) उत्पादन की दिशा में भी छत्तीसगढ़ तेजी से प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण पर तीव्र गति से कार्य हो रहा है, और नए औद्योगिक पार्क भी स्थापित किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र को औद्योगिक पार्क स्थापित करने हेतु विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया है। उन्होंने समिट में उपस्थित उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने और यूनिट स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया।

प्रशिक्षित जनशक्ति एवं लॉजिस्टिक नीति का लाभ उठाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के सभी विकासखंडों में स्किल इंडिया के सेंटर प्रारंभ कर दिए गए हैं, जिससे उद्योगों को प्रशिक्षित जनशक्ति की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि निवेशकों को नई लॉजिस्टिक नीति का भी लाभ मिलेगा। इस नीति के अंतर्गत ड्राय पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो आदि की स्थापना पर भी अनुदान प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सेंट्रल इंडिया में स्थिति होने के कारण लॉजिस्टिक के क्षेत्र में असीम संभावनाएँ हैं। एक्सप्रेसवे, रेलवे और राजमार्गों के माध्यम से देश के चारों दिशाओं में बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ स्टील सेक्टर को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने रायपुर-दुर्ग-भिलाई जैसे शहरों को

शामिल कर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में एक बड़े स्टील क्लस्टर के विकास की योजना की जानकारी भी दी।

250 से अधिक औद्योगिक संस्थान हुए समिट में शामिल

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित इस ग्रीन स्टील और माइनिंग समिट में पूर्वी भारत के पांच राज्यों-पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़-के 250 से अधिक स्टील और पावर सेक्टर से जुड़े औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में उद्योगों की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने सीआईआई द्वारा आयोजित औद्योगिक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

स्थानीय स्तर पर मिलेगी वैश्विक गुणवत्ता की सुविधा

राज्य में APEDA कार्यालय की स्थापना से अब फाइटो-सेनेटरी प्रमाणपत्र, गुणवत्ता प्रमाणन, लैब टेस्टिंग, और निर्यात से जुड़ी प्रक्रियाएं यहीं पूरी की जा सकेंगी। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि किसानों और निर्यातकों की लागत में भी कमी आएगी। APEDA कार्यालय से फल, सब्जियाँ, चावल, GI टैग वाले उत्पाद, मिलेट्स और अन्य कृषि उत्पादों का सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात आसान होगा। इससे उत्पादों को उचित दाम, व्यापारियों को नए बाजार, और राज्य को वैश्विक मंच पर पहचान मिलेगी।

किसानों की आय और ज्ञान दोनों में वृद्धि

निर्यात से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही, नई तकनीकों, गुणवत्ता नियंत्रण, आधुनिक पैकेजिंग और अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग की जानकारी और प्रशिक्षण उन्हें स्थानीय स्तर पर मिल सकेगा।

निर्यात बुनियादी ढांचे को मिलेगा प्रोत्साहन

APEDA न केवल प्रमाणन और ब्रांड प्रमोशन में सहयोग करता है, बल्कि निर्यात बुनियादी ढांचे के निर्माण और रख-रखाव में भी सहायता करता है। इससे राज्य में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस जैसे सुविधाओं का विकास होगा, जिससे कृषि व्यापार को नई गति मिलेगी।

एयरोस्पेस में निवेश का नया केंद्र बनने की ओर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य अब केवल खनिज और कृषि प्रधान राज्य नहीं रह गया है, बल्कि तकनीकी नवाचार और रणनीतिक उद्योगों का नया गढ़ बनकर उभरने की दिशा में अग्रसर है। इस परिवर्तन की आधारशिला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में रखी गई है, जिन्होंने न केवल राज्य की औद्योगिक नीतियों को समकालीन और रोजगारोन्मुख बनाया, बल्कि रक्षा, एयरोस्पेस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इन उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए पृथक औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई। यह पैकेज न केवल इन क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि राज्य के युवाओं के लिए सेवा और रोजगार के अवसरों के नए द्वार भी खोलेगा।

आयरन ओर भंडार बस्तर क्षेत्र के विकास का ध्यान

छत्तीसगढ़ राज्य की नयी "औद्यागिक विकास नीति 2024-30" में उद्योगों की नवीन तकनीक को अपनाने हेतु प्रोत्साहित कियाजा रहा है। यदि स्टील उद्योगों द्वारा इस दिशा में कार्य किया जाता है तो राज्य शासन की ओर से मदद की जाएगी। श्री देवांगन ने कहा की राज्य के आयरन ओर भंडार बस्तर क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के द्वारा कोर-सेक्टर के स्टील इकाईयों तथा अन्य कोर सेक्टर की इकाईयों को पात्रतानुसार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त 50 प्रतिशत तक आयरन ओर रायल्टी तथा 100 प्रतिशत कोल पर रायल्टी एवं राज्य को प्राप्त होने वाले सेस की प्रतिपूर्ति 150 प्रतिशत तक वर्ष तक किये जाने का प्रावधान भी किया गया है।

पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे की अंतिम कृति "मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ" का हुआ विमोचन

- **हास्य कवि डॉ. दुबे अपनी हँसती- गुदगुदाती कविताओं के माध्यम से सदैव रहेंगे हमारे बीच जीवितः साय**
- **पद्मश्री डॉ. दुबे ने देश-विदेश में बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान : डॉ. रमन सिंह**

> मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वर्गीय पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे की जयंती के अवसर पर उनकी अंतिम काव्य कृति "मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ" के विमोचन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। यह आयोजन राजधानी स्थित मैक कॉलेज ऑडिटोरियम में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा के संवर्धन में अमूल्य योगदान दिया। वे एक ऐसे हास्य कवि थे, जिन्होंने देश-विदेश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया और राज्य को गौरवान्वित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज हम डॉ. सुरेंद्र दुबे जी की अंतिम कृति का विमोचन कर रहे हैं। वे आज भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, और उनकी अनुपस्थिति हम सभी को गहराई से खल रही है। यह छत्तीसगढ़ और साहित्य जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा "डॉ. दुबे जी एक महान कवि थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा को अपनी

कविताओं के माध्यम से देश और दुनिया में जन-जन तक पहुँचाया"। वे जहाँ भी गए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भाषा और पहचान को साथ लेकर गए। उनकी कविताएँ केवल हँसी नहीं बिखेरती थीं, बल्कि गहरे सामाजिक संदेश भी देती थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि "मुझे अनेक मंचों पर उनकी कविताएँ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे हास्य कवि होने के साथ ही एक अत्यंत सौम्य, सरल और संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी भी थे। उनके मन में देश, प्रदेश और समाज के लिए गहरी करुणा और जागरूकता थी। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। वे अपने शब्दों और विचारों के माध्यम से हमारे बीच सदैव जीवित रहेंगे।"

सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक स्वाभिमान को दी नई दिशा

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि डॉ. सुरेन्द्र दुबे छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य और लोक संस्कृति के ऐसे प्रखर प्रतिनिधि थे, जिन्होंने अपने लेखन, नाट्यकर्म और जनसंवाद के माध्यम से प्रदेश को सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक स्वाभिमान की नई दिशा दी।

कार्यक्रम में धरसीवां विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा ने आलेख का पाठन किया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन स्वर्गीय डॉ. सुरेन्द्र दुबे की धर्मपत्नी श्रीमती शशि दुबे द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्री सुरेन्द्र दुबे फाउंडेशन द्वारा किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन, दुर्ग सांसद विजय बघेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण एवं साहित्यकार उपस्थित थे।

हर घर बनेगा बिजली घर

छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उनकी यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और सतत विकास के बड़े लक्ष्यों को भी हासिल करेगी। साथ ही जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्यों में योगदान सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में घर-घर रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित कर लोगों को प्रदूषण मुक्त, मुफ्त और निरंतर बिजली देने की परिकल्पना की गई है। इसके माध्यम से प्रत्येक उपभोक्ता को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर उनके मासिक खर्चों में भी उल्लेखनीय कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

हर नागरिक की होगी भागीदारी

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्रता रखने वाले सभी नागरिक जिनके पास वैध बिजली कनेक्शन और उपयुक्त छत है, वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि योजना के अंतर्गत एक बार सोलर पैनल स्थापित होने के बाद उपभोक्ता को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे न सिर्फ बिजली बिलों का झंझट समाप्त होगा, बल्कि यदि आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन होता है, तो उसे ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी ली जा सकती है।

मिलेगी डबल सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवॉट से 3 किलोवॉट तक के सौर संयंत्र लगाने पर प्रति वॉट 45 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख 8 हजार रुपये तक की सब्सिडी केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दी जा रही है। इसमें राज्य सरकार ने भी अपनी हिस्सेदारी जोड़ दी है, जिससे उपभोक्ताओं को डबल सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा।

स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण

छत्तीसगढ़ सरकार जीरो कार्बन एमिशन नीति को साकार रूप देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को प्राथमिकता दे रही है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 15 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। इसे बढ़ाकर सरकार ने वर्ष 2047 तक 45 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। यह नीति न केवल वर्तमान, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हरित और सतत भविष्य सुनिश्चित करेगी।

बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा क्रांति से रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। इससे सोलर पैनल के निर्माण, स्थापना, रखरखाव आदि जैसे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं राज्य की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।

योजना के फायदे

केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से डबल सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलेगा। एक बार सौर पैनल की स्थापना के बाद 20-25 वर्षों तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। लोगों को निरंतर विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। बार-बार बिजली गुल होने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा बिजली बेचने से अतिरिक्त आमदनी होगी। साथ ही स्वच्छ, हरित और पर्यावरण हितैषी जीवनशैली को बढ़ावा मिलेगा।

नुकसान भी पहुंचा सकता है ज्यादा चुकंदर सेवन

अगर चुकंदर को सही मात्रा में और सही तरीके से कंज्यूम किया जाए, तो सेहत पर ढेर सारे पॉजिटिव असर पड़ सकते हैं। वहीं, अगर आप जरूरत से ज्यादा चुकंदर का सेवन करते हैं, तो आपकी सेहत पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि ज्यादा मात्रा में चुकंदर का सेवन करने की वजह से आपको सेहत से जुड़ी किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

बढ़ सकता है किडनी स्टोन का खतरा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चुकंदर में ऑक्सलेट की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। यानी अगर आप जरूरत से ज्यादा चुकंदर का सेवन करते हैं, तो किडनी में स्टोन होने का खतरा बढ़ सकता है। अगर आप किडनी स्टोन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह लिए बिना चुकंदर या फिर चुकंदर के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए।

बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है गट हेल्थ

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक चुकंदर में पाए जाने वाले तत्व आपकी गट हेल्थ पर बुरा असर डाल सकते हैं। जरूरत से ज्यादा चुकंदर का सेवन करने की वजह से पेट में ऐंठन भी हो सकती है। पेट से जुड़ी समस्याओं की चपेट में आने से बचने के लिए आपको लिमिट में रहकर ही चुकंदर का सेवन करना चाहिए। दरअसल, किसी भी चीज की अति सेहत को डैमेज करने का काम कर सकती है।

लिवर पर पड़ सकता है नेगेटिव असर

स्टडीज के मुताबिक जो लोग चुकंदर का ज्यादा सेवन करते हैं, उन्हें लिवर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चुकंदर में पाए जाने वाले तत्व, अगर शरीर में ज्यादा मात्रा में पहुंच जाएं, तो लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्यादा चुकंदर कंज्यूम करने के कारण हड्डियों से जुड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं।

उस नदी की कहानी, जिसने धराली को तबाह कर दिया

चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है. सोशल मीडिया पर घटना के जो वीडियो वायरल हैं, उनमें स्थानीय लोग चिल्लाकर एक-दूसरे को आपदा की चेतावनी और जान बचाकर भागने की अपील करते हुए सुने जा सकते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे घर और कई मंजिला इमारतें पानी और इसके साथ आए मलबे के तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह ढह गई. उत्तराखंड सरकार का दावा है कि राहत और बचाव कार्य जोर-शोर से चलाए जा रहे हैं और इसमें आपदा प्रबंधन बलों के अलावा, सेना और अर्धसैनिक बलों की मदद भी ली जा रही है.

इन सबके बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा में है- वो है खीर गंगा नदी, जो भागीरथी में जाकर मिलती है. धराली उत्तरकाशी जिले का एक कस्बा है और गंगोत्री की ओर बढ़ते हुए हर्षिल घाटी का हिस्सा है. ये घाटी चारधामों में से एक गंगोत्री धाम की यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए एक अहम पड़ाव भी है. यहाँ से गंगोत्री तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है. भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो यह

समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है, और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है. धराली क़स्बे में हिमालय की ऊँची चोटियों में उतरकर आती है खीर गंगा. यूँ तो यह तकरीबन पूरे साल शांत और धीमे प्रवाह में बहती है, लेकिन बरसात में अपना उग्र रूप दिखा देती है. मंगलवार को खीर गंगा ने जैसा रौद्र रूप दिखाया, इतिहास के जानकार और भूगर्भ विज्ञानी भी मानते हैं कि पहले भी खीर गंगा में भीषण बाढ़ आ चुकी है. भूगर्भ विज्ञानी प्रोफेसर एसपी सती बताते हैं कि 1835 में खीर गंगा में सबसे भीषण बाढ़ आई थी. तब नदी ने सारे धराली क़स्बे को पाट दिया था. बाढ़ से यहाँ भारी मात्रा में मलबा (गाद) जमा हो गया था. उनका दावा है कि अभी जो भी बसावट है, वह उस समय नदी के साथ आई गाद पर स्थित है. पिछले कुछ सालों में खीर गंगा में पानी का तेज बहाव आने की घटनाएँ हुई हैं, कई घर इस बाढ़ में बहे भी हैं, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई थी.

हिमालय के इतिहास और पर्यावरण के विशेषज्ञ माने जाने वाले इतिहासकार डॉ. शेखर पाठक भी मानते हैं कि ये इलाक़ा बेहद संवेदनशील है और भूस्खलन और एवलांच जैसे हादसों की संभावना यहाँ बनी रहती है. हिमालय की चौखंभा वेस्टर्न रेंज का ये इलाक़ा है. साल 1700 में जब गढ़वाल में परमार राजवंश का शासन था. तब भी बड़ा भूस्खलन होने से झाला में 14 किलोमीटर लंबी झील बन गई थी और इसका प्रमाण आज भी देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ भागीरथी ठहरी हुई लगती है. डॉक्टर पाठक बताते हैं कि 1978 में धराली से नीचे उत्तरकाशी की तरफ आते हुए 35 किलोमीटर दूर डबराणी में एक डैम टूट गया था, इससे भागीरथी में बाढ़ आ गई थी और कई गाँव बह गए थे. इसके बाद धराली और आसपास के इलाक़ों में कई बार बादल फटने, भूस्खलन की घटनाएँ हुई, लेकिन कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई थी. रही बात, खीर गंगा के नाम को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही कई कहानियों की, तो शेखर पाठक इन्हें बस 'सुनी-सुनाई बातें' ही मानते हैं. उन्होंने कहा, "ये नदी पहले ग्लेशियर और फिर घने जंगलों से होकर बहती है, इसलिए इसका पानी शुद्ध रहता है. मतलब कई दूसरी नदियों की तरह इसमें चूने का पानी मिला हुआ नहीं है. इसलिए इसे खीर नदी कहा जाता है".

बादल फटना हिमालय क्षेत्र में सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है. इसकी वजह है बहुत कम समय में किसी छोटे इलाक़े में भारी बारिश का होना. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, बादल फटने की परिभाषा है- जब किसी 20 से 30 वर्ग किलोमीटर इलाक़े में, एक घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो जाए. विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इन घटनाओं की संभावना लगातार बढ़ रही है. पहले ऊँचाई वाले इन इलाक़ों में बर्फ गिरती थी, ग्लेशियर बनते थे, बारिश बहुत कम होती थी. लेकिन अब बर्फ कम गिरती है और बारिश भी खूब होती है. इसकी वजह है जलवायु परिवर्तन और इनका असर ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आता है. साल 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी),रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में बताया था कि बादल फटने की ज़्यादातर घटनाएँ आमतौर पर 2000 मीटर से अधिक की ऊँचाई वाले क्षेत्रों में होती हैं. इनमें हिमालय की कई आबादी वाली घाटियाँ भी शामिल हैं.

जो भी भारत पर आक्रमण करेगा, वह पाताल में भी सुरक्षित नहीं रहेगाः मोदी

◦ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, उसे अपने आर्थिक हितों के प्रति सतर्क रहना होगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लगभग 2,200 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सावन के पावन माह में वाराणसी के परिवारों से मिलकर उनसे अपनी हार्दिक भावनाएं व्यक्त की। वाराणसी के लोगों के साथ अपने गहरे भावनात्मक जुड़ाव का उल्लेख करते हुए, श्री मोदी ने शहर के प्रत्येक परिवार के सदस्य के प्रति अपना आदरपूर्वक अभिवादन किया। श्री मोदी ने सावन के पावन महीने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के किसानों से जुड़ने पर भी संतोष व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह उनकी वाराणसी की पहली यात्रा है। उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को याद करते हुए कहा कि इसमें 26 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। श्री मोदी ने पीड़ित परिवारों, विशेषकर इस त्रासदी से प्रभावित बच्चों और बेटियों के दुःख को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि उनका हृदय इस दुःख से अत्यंत व्याकुल है और प्रधानमंत्री ने बताया कि उस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ से सभी शोक संतप्त परिवारों को यह कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का उनका वादा पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भगवान महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भगवान महादेव के चरणों में समर्पित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि हाल के दिनों में, वे वाराणसी में शिव भक्तों की दिव्य छवियां देख रहे थे, विशेषकर सावन के पहले सोमवार को, जब तीर्थयात्री बाबा विश्वनाथ का पवित्र जलाभिषेक करने के लिए निकलते हैं। उन्होंने गौरी केदारनाथ से

अपने कंधों पर पवित्र गंगाजल लाते यादव बंधुओं के मनोरम दृश्य का उल्लेख करते हुए इसे बेहद मनमोहक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डमरू की ध्वनि के साथ गलियों में जीवंत ऊर्जा का वातावरण अलौकिक था। श्री मोदी ने सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव के दर्शन करने की अपनी व्यक्तिगत इच्छा व्यक्त की। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी उपस्थिति महादेव के भक्तों को असुविधा का कारण बन सकती है या उनके दर्शन में बाधा बन सकती है, इसलिए वे यहीं से भगवान भोलेनाथ और मां गंगा को प्रणाम करते हैं।

भारत के तमिलनाडु में शैव परंपरा के एक प्राचीन ऐतिहासिक केंद्र गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर और एक हजार वर्ष प्राचीन स्मारक की कुछ दिन पहले की अपनी यात्रा का स्मरण करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि इस मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध राजा राजेंद्र चोल ने करवाया था, जो उत्तर और दक्षिण को प्रतीकात्मक रूप से एक करने के लिए उत्तर भारत से गंगाजल लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि एक हजार वर्ष पहले, भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और शैव परंपरा के लिए प्रतिबद्धता के माध्यम से, राजेंद्र चोल ने ष्एक भारत, श्रेष्ठ भारतष के विजन का उद्घोष किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज, काशी-तमिल संगमम जैसी पहलों के माध्यम से उस विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गंगईकोंडा चोलपुरम की अपनी हाल की यात्रा के दौरान, वे अपने साथ गंगाजल लेकर गए थे और मां गंगा के आशीर्वाद से, अत्यंत पवित्र वातावरण में पूजा संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर देश में एकता की भावना को जगाते हैं, जिससे ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों को सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की एकता ऑपरेशन सिंदूर की ताकत बनी।

वाराणसी में आयोजित किसान महोत्सव के भव्य आयोजन का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश भर के 10 करोड़ किसान भाई-बहनों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के दौरान 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। श्री मोदी ने कहा कि बाबा के आशीर्वाद से वाराणसी में विकास की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों और देश के सभी किसानों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ही वाराणसी में सांसद पर्यटक गाइड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आने वाले दिनों में, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और सांसद रोजगार मेला जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जायेगा। उन्होंने इन पहलों की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ऐसी पहलों के लिए प्रशासन की भी सराहना की।

सरकार किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही

मोदी ने इस बात पर बल दिया कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने पिछली सरकारों से इसकी तुलना करते हुए कहा कि उस समय किसानों के नाम पर की गई एक भी घोषणा शायद ही कभी पूरी हुई हो। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अपने वादों को पूरा करती है,

और पीएम-किसान सम्मान निधि को सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। वर्ष 2019 में पीएम-किसान सम्मान निधि के शुभारंभ के समय को याद करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि कुछ प्रमुख विपक्षी दल तरह-तरह की अफवाहें फैला रहे थे, जबकि कुछ ने दावा किया कि चुनाव के बाद भुगतान बंद हो जाएगा और कुछ ने सुझाव दिया कि हस्तांतरित धन वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह विपक्ष के असली चरित्र को दर्शाता है, जो केवल किसानों और देश के लोगों को गुमराह करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके शुभारंभ के बाद से पीएम-किसान सम्मान निधि बिना किसी रुकावट के जारी है। उन्होंने बताया कि अब तक 3.75 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में, लगभग 2.5 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें इस योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वाराणसी के किसानों को लगभग 900 करोड़ रुपये मिले हैं। उन्होंने इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह बताया कि धनराशि बिना किसी कटौती या कमीशन के किसानों तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि यह उनकी सरकार द्वारा स्थापित एक स्थायी व्यवस्था है- इसमें कोई लीकेज नहीं होगी, तथा गरीबों के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। "जो क्षेत्र जितना पिछड़ा होगा, उसे उतनी ही ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी" के विकास मंत्र को दोहराते हुए, श्री मोदी ने घोषणा की कि इस महीने की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने एक बड़ी नई पहल- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना- को स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस पहल का ध्यान उन जिलों पर होगा जो पिछली सरकारों की दोषपूर्ण नीतियों के कारण पिछड़ गए थे- कम कृषि उत्पादन वाले क्षेत्र और जहा किसानों की आय सीमित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से उत्तर प्रदेश के भी लाखों किसानों को सीधा

लाभ होगा।प्रधानमंत्री ने बल देकर कहा कि हमारी सरकार किसानों के जीवन में बदलाव लाने, उनकी आय बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। हम बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए देश भर में लाखों करोड़ रुपये की सिंचाई योजनाएं लागू की जा रही हैं।

दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों की शक्ति देखी

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों की शक्ति और भारत की वायु रक्षा प्रणालियों, स्वदेशी मिसाइलों और ड्रोनों की प्रभावशीलता देखी, जिसने आत्मनिर्भर भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने विशेष रूप से भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति ने देश के हर दुश्मन में भय पैदा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सांसद के रूप में, श्री मोदी ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि ब्रह्मोस मिसाइलें जल्द ही राज्य में निर्मित होंगी। उन्होंने घोषणा की कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन शुरू हो रहा है और कई प्रमुख रक्षा कंपनियां उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे में संयंत्र स्थापित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में निर्मित हथियार भारत की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री ने जनता से पूछा क्या उन्हें इस उपलब्धि पर गर्व है। उन्होंने घोषणा की कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई और गलत कार्य किया, तो उत्तर प्रदेश में बनी मिसाइलें आतंकवादियों को धूल चटा देंगी।

उत्तर प्रदेश में तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास और बड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के राज्य में निवेश के आकर्षित होने पर श्री मोदी ने इस बदलाव का श्रेय अपनी सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों को दिया। उन्होंने वर्तमान परिदृश्य की तुलना पिछली सरकारों से की, जहां अपराधी बेखौफ होकर काम करते थे और निवेशक राज्य में आने से हिचकिचाते थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब अपराधी भयभीत हैं और निवेशक उत्तर प्रदेश के भविष्य में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विकास की इस गति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई दी और इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि वाराणसी में विकास का महाअभियान निरंतर जारी है।

एक नवीन रेल ओवरब्रिज, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहल, वाराणसी में स्कूलों का पुनर्निर्माण, एक होम्योपैथिक कॉलेज का निर्माण और मुंशी प्रेमचंद की विरासत को संरक्षित करने के प्रयास के रूप में आज शुभारंभ की गई कई परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं एक भव्य, दिव्य और समृद्ध वाराणसी के निर्माण में तेजी लाएंगी। उन्होंने सेवापुरी की यात्रा को सौभाग्य की बात बताया और इसे मां कालका देवी की चौखट बताया। उन्होंने मां कालका देवी के चरणों में नमन करते हुए इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि सरकार ने मां कालका धाम का सौंदर्यीकरण किया है, इसे और अधिक भव्य बनाया है और मंदिर तक पहुंच को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री ने सेवापुरी के क्रांतिकारी इतिहास को याद किया और स्वतंत्रता संग्राम में इसके महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यही वह सेवापुरी है जहां महात्मा गांधी का स्वप्न साकार हुआ था, जहां हर घर में पुरुषों और महिलाओं के हाथों में चरखा था। श्री मोदी ने एक सार्थक संयोग का भी उल्लेख किया जिसमें चांदपुर-भदोही रोड जैसी परियोजनाओं के माध्यम से, वाराणसी के बुनकर अब भदोही के बुनकरों से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बनारसी रेशम के कारीगरों और भदोही के कारीगरों दोनों को लाभ होगा।

श्री मोदी ने आर्थिक प्रगति पर चर्चा करते हुए, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि वाराणसी बुद्धिजीवियों का शहर है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्तमान में अनेक अनिश्चितताओं और अस्थिरता के माहौल का सामना कर रही है। ऐसे में, दुनिया भर के देश अपने-अपने हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है। इसलिए, उन्होंने कहा कि भारत को अपने आर्थिक हितों के प्रति सजग रहना होगा। उन्होंने बल देते हुए कहा कि किसानों और लघु उद्योगों का कल्याण सर्वोपरि है और सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है।

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कितना पानी पीना चाहिए

किडनी इंसान के शरीर के उन अहम अंगों में से एक है, जिस पर शरीर को स्वस्थ रखने की कई जिम्मेदारियां होती हैं. अक्सर डॉक्टर सलाह देते हैं कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित मात्रा में नमक खाएं, ज्यादा चीनी से परहेज करें और पेनकिलर्स का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के न करें. किडनी पर ज्यादा दबाव न पड़े, इसके लिए कई अन्य उपाय भी सुझाए जाते हैं.

तो क्या किडनी को ठीक रखने के लिए एक निश्चित मात्रा में पानी पीना जरूरी है?

इस रिपोर्ट में हम ऐसे ही कुछ आम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे. किडनी

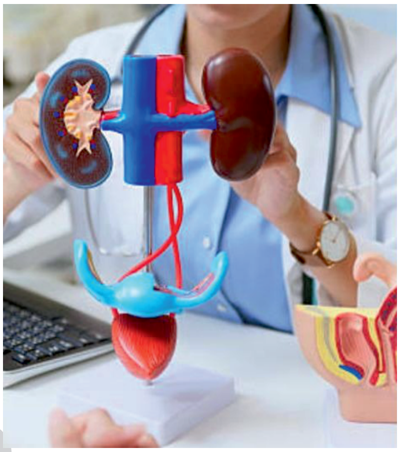

हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने का काम करती है. यह सोडियम और पोटाशियम जैसे तत्वों की मात्रा को नियंत्रित करती है. विशेषज्ञ कहते है कि किडनी शरीर से उन गैर-जरूरी चीजों को बाहर निकालती है, जो हम खान-पान या अन्य तरीकों से लेते हैं. और वो तत्व भी जो शरीर में मेटाबॉलिज्म के जरिए बनते हैं. किडनी शरीर में कई तरह के हार्मोन भी बनाती है, जिसमें खून बनाने वाला हार्मोन, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन और इलेक्ट्रोलाइट को संतुलित रखने वाला हार्मोन शामिल है. हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हर प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है. जैसे, हृदय की हर कोशिका सही ढंग से काम करे, इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट की एक तय मात्रा आवश्यक होती है. यदि इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित हो जाए तो दिमाग के कामकाज पर असर पड़ सकता है, मांसपेशियों की कार्यक्षमता घट सकती है और नर्वस सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है.

किडनी रोग विशेषज्ञ कहते हैं, किडनी अगर सही तरीके से काम न करे तो विटामिन डी लेने का भी कोई फायदा नहीं होगा. चाहे आप कितना भी विटामिन डी ले लें, इससे शरीर को कोई लाभ नहीं होगा. किडनी को शरीर के लिए एक तरह का "वोल्टेज स्टेबिलाइजर" भी कहा जाता है. अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा पानी पी ले तो किडनी अतिरिक्त पानी को शरीर से बाहर निकाल देती है. किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोज कितना पानी पीना चाहिए इसकी कोई तय मात्रा नहीं है. हमारे शरीर को कितने पानी की जरूरत है, यह शरीर खुद बता देता है. हमें प्यास लगना इसी का संकेत है. वह बताते हैं कि शरीर से कई तरीकों से पानी निकलता रहता है, जैसे पसीने और सांस के जरिए. इसके अलावा कुछ प्रक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो दिखती नहीं हैं, लेकिन उनमें भी पानी शरीर से बाहर निकलता है. ऐसे में किसी वयस्क व्यक्ति के लिए कम से कम 700 से 800 मिलीलीटर पानी जरूरी होता है. हालांकि शरीर को जरूरी मात्रा में जल केवल सादा पानी पीकर

ही नहीं मिलता. दूध, फलों का रस या छाछ जैसे तरल पदार्थों के जरिए भी शरीर में पानी पहुंचता है.यह भी ध्यान देना जरूरी है कि किसी व्यक्ति को कितने पानी की जरूरत है, यह उसकी उम्र, शारीरिक सक्रियता और वातावरण पर निर्भर करता है. अगर कोई व्यक्ति गर्म जलवायु में रहता है तो उसे ज़्यादा पानी की जरूरत होगी.

ज़्यादा पानी पी लिया तो निकाल देगी किडनी

जो लोग दिल या किडनी की बीमारी से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए पानी की मात्रा थोड़ी सीमित की जाती है, ताकि उन अंगों पर ज़्यादा दबाव न पड़े. किडनी शरीर में पानी की मात्रा को भी संतुलित करती है. अगर आपने ज़्यादा पानी पी लिया है तो किडनी उसे बाहर निकाल देगी, और अगर कम पी रहे हैं तो वही पानी शरीर में बचाकर रखेगी. इसकी कोई तय मात्रा नहीं है कि किसी को कितना पानी पीना चाहिए. हालांकि सामान्यत: एक स्वस्थ वयस्क को रोजाना दो से तीन लीटर पानी पीना चाहिए. शरीर में पानी की जरूरत व्यक्ति के शरीर के आकार पर भी निर्भर करती है. उदाहरण के तौर पर छोटे बच्चों को वयस्कों की तुलना में कम पानी की जरूरत होती है. किडनी को स्वस्थ रखने का सबसे बुनियादी तरीका यह है कि आप संतुलित भोजन लें, शरीर का वजन नियंत्रित रखें और नियमित रूप से शारीरिक रूप से सक्रिय रहें.

भारत में ज्यादातर लोग करते है ज्यादा नमक का सेवन

मध्य-पूर्व के देशों में किडनी की बीमारियां कम देखी जाती हैं, क्योंकि वहां लोग नमक कम खाते हैं. जबकि भारत में ज्यादातर लोग ज्यादा नमक का सेवन करते हैं, जिससे किडनी पर असर पड़ता है. जब कोई व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में नमक या चीनी लेता है, तो उसे संतुलित बनाए रखने के लिए किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. यही दबाव लंबे समय में किडनी की कार्यक्षमता को

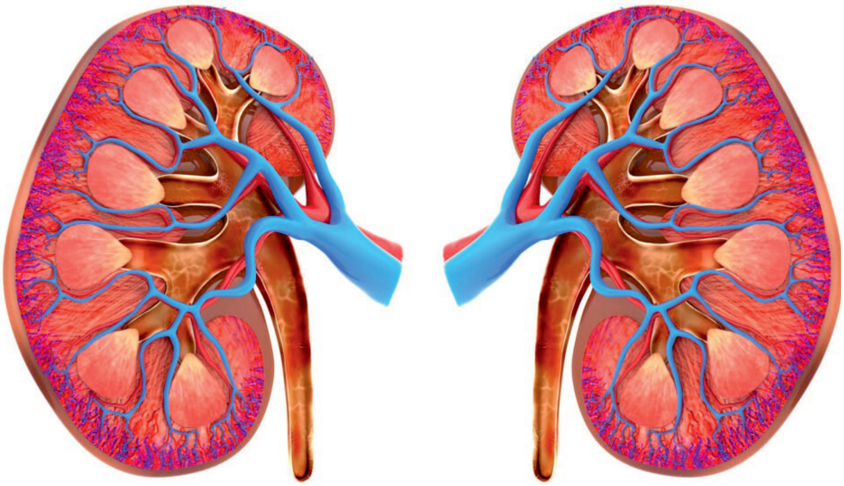

प्रभावित कर सकता है. इसके अलावा, कई लोग लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर से जूझते हैं, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लेते. ड्क्टरों के मुताबिक, हाई ब्लड प्रेशर का सीधा असर किडनी पर पड़ता है, क्योंकि उसे ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है. इसलिए अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो उसे डॉक्टर की सलाह से दवाओं के जरिए नियंत्रित करना चाहिए.किडनी को स्वस्थ रखने के लिए एक और जरूरी सलाह यह दी जाती है कि धूम्रपान से बचें, क्योंकि तंबाकू और उससे बने उत्पादों का असर भी सीधे किडनी पर पड़ता है.

पाठशालाओं में जब बजेगी घण्टी, होगी स्कूलों में शिक्षकों की गारंटी

- युक्ति युक्तकरण से प्रदेश के शिक्षकविहीन शालाओ में हुई नियमित शिक्षको की नियुक्ति
- शैक्षणिक माहौल बदलेगा,गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी'
- मोदी की गारण्टी को पूरा करने के साथ ही पाठशालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था की दिशा में उठाया गया क्रांतिकारी कदम

टन... टन.. टन... टन... घण्टी की यह आवाज अब फिर से स्कूलों में सुनाई देने ही वाली है। ग्रीष्म अवकाश के बाद लम्बे दिनों के अंतराल में क्लास रूम की चहल-पहल में क, ख, ग और ए, बी, सी, डी की शोर भी सुनाई देगी। बीते हर साल की तरह स्कूलों के पट खुलने के साथ पहली बार स्कूल आने वाले विद्यार्थियों के माथे पर तिलक लगाएं जाएंगे। मिठाइयां खिलाई जाएंगी और कलम,किताब, ड्रेस देकर उनका अभिनंदन भी किया जाएगा। इन सबके बीच इस साल कुछ नया भी होगा। पाठशालाओं के दहलीज पर कदम रखकर भविष्य बनाने आएँ दूरस्थ क्षेत्र के उन हजारों विद्यार्थियों को नियमित शिक्षक भी मिलेंगे, जहाँ कोई शिक्षक पदस्थ नहीं था। प्रदेश के लगभग 6 हजार एकल शिक्षकीय विद्यालय में अतिशेष शिक्षको का समायोजन किया गया है, जिससे 4 हजार 721 विद्यालय लाभान्वित हुए है। वही युक्ति युक्तकरण से पूर्व प्रदेश भर में 453 शिक्षकविहीन विद्यालय थे। इन विद्यालयों में से 446 विद्यालयों में अतिशेष शिक्षको की पदस्थापना कर राज्यशासन ने शिक्षक की कमी से वंचित विद्यार्थियों के भविष्य को गढ़ने के साथ ही पाठशालाओं की घण्टी बजने के साथ ही शिक्षको की गारंटी भी सुनिश्चित कर दी है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश की कमान सम्हालने के साथ ही अनेक साहसिक निर्णय लेकर मोदी की गारण्टी को पूरा करने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शपथ लेने के पश्चात केबिनेट की पहली ही बैठक में 18 लाख पीएम आवास निर्माण के लिए निर्णय लेने के बाद, 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी, 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी, तेन्दूपत्ता खरीदी में प्रति मानक बोरा की राशि को बढ़ाते हुए चार हजार से 5500 करने के साथ ही किसानों को दो साल के बकाया बोनस की राशि और मोदी की गारण्टी में शामिल योजनाओं को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया।

यह भी सर्वविदित ही है कि प्रदेश के विद्यालयों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी थी। खासकर प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में अनेक ऐसे विद्यालय थे जहाँ लम्बे समय से शिक्षक नहीं थे तो कुछ में एकमात्र शिक्षक ही पदस्थ थे। राज्य शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रदेश भर में शिक्षको की स्थितियों को जब परीक्षण किया तो पाया कि छात्र संख्या के आधार पर एक शिक्षक के पीछे विद्यार्थियों की जितनी संख्या होनी चाहिए थीं,इसमे भी अनेक खामी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम थी,लेकिन शिक्षकों की संख्या अधिक, अनेक विद्यालयों में गणित, जीव-विज्ञान, रसायन, भौतकी, अंग्रेजी सहित महत्वपूर्ण विषयों की शिक्षकों की कमी थी तो कई ऐसे भी विद्यालय थे जहाँ एक से अधिक विषयों के शिक्षक थे। इन्हीं असमानताओं की वजह से प्राथमिक शाला से लेकर हायर सेकण्डरी के हजारों

विद्यार्थियों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी वह मिल नहीं पा रही थी। विद्यार्थियों को स्कूल की दहलीज में पहली बार कदम रखने से लेकर कैरियर बनाने के महत्वपूर्ण पड़ाव में शिक्षको की कमी बाधा साबित हो रही थी। राज्य शासन ने जब अतिशेष शिक्षको की संख्या निकालकर युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई तो निःसंदेह ऐसे विद्यालयों की तस्वीर ही बदल गई है। दूरस्थ क्षेत्र के विद्यार्थियों ही नहीं पालकों में भी खुशी की लहर है। अब उनके स्कूलों में भी शिक्षक की व्यवस्था होगी यह जानकर वे भी स्कूल आने के लिए रोमांचित है।

राज्य शासन द्वारा युक्ति युक्तकरण के लिए गए फैसले और अपनाई गई प्रक्रिया से शिक्षकविहीन 453 स्कूलों में से 446 अब शिक्षकविहीन नहीं रहेंगे। 5936 एकलशिक्षकीय विद्यालय में से 4721 में अब एकलशिक्षकीय नहीं होगी। यहाँ कम से कम दो या तीन शिक्षक अध्यापन कराएंगे। खासबात यह भी है कि सुदूरवर्ती इलाकों के विद्यालयों जहां गरीब और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या अधिक है वहाँ के सरकारी स्कूलों में भी अब पर्याप्त शिक्षक होंगे।

युक्ति युक्तकरण से बस्तर संभाग के अंतर्गत बस्तर में 25, बीजापुर के 76, नारायणपुर के 14, सुकमा के 29, कोंडागांव के 10 प्राथमिक शाला शिक्षकविहीन थे। अब सभी विद्यालय में शिक्षक पदस्थ कर दिए गए हैं। इसी तरह गरियाबंद के 17, महासमुंद के 14, कोरबा के 14, रायगढ़ के 21, सरगुजा के 14, बालोद के 16, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के 13, बलरामपुर जिले के 14 प्राथमिक शाला शिक्षकविहीन थे। इन सभी विद्यालयों में अब अतिशेष शिक्षको के समायोजन के पश्चात वर्षों से रिक्त स्थानों में नियमित शिक्षको की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। प्रदेश के मिडिल स्कूलो में भी एकलशिक्षकीय से द्वि शिक्षकीय और कई विद्यालयों में तीन शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। शासन के इस फैसले से पालकगण भी खुश है। कल तक शिक्षको की कमी से जूझते विद्यालय में अपने बच्चों को भेजने के साथ ही जो चिंतित थे अब उनके आँखों मे अपने बच्चों की बेहतर भविष्य का सपना सजने लगा है।

'गणित, भौतकी, रसायन, जीवविज्ञान में नहीं होंगे कमजोर'

प्राथमिक और माध्यमिक शाला के अतिशेष शिक्षकों को दूरस्थ क्षेत्रों के शिक्षकविहीन और एकलशिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थ किए जाने से जहाँ दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षा की नींव मजबूत होगी वहीं मिडिल और हाई स्कूलों से निकलने के बाद हायर सेकण्डरी में पहुँचने वाले विद्यार्थियों को भी अब गणित, भौतकी, रसायन, जीवविज्ञान, अंग्रेजी जैसे विषयों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। विद्यालय में सम्बंधित विषय का पाठ्यक्रम संचालित होने के बाद भी विषय के व्याख्याता नहीं होने का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता था। अतिशेष व्याख्याताओं का पदस्थापना रिक्त विषय वाले विद्यालयों में हो जाने से उन्हें भी स्कूल में संबंधित विषयों को पढ़ने में आसानी होगी और वे अपने विषय शिक्षक से उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों में कला विषय चयन करने के अलावा गणित, विज्ञान विषय चयन करने में रुचि जागेगी।

'पाठ्यक्रम समय पर होगा पूरा'

अतिशेष शिक्षको के समायोजन से दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा। उनके विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक पदस्थ होंगे और समय पर सभी विषयों के कालखण्ड भी होंगे। इस व्यवस्था से विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम समय पर पूरा होगा। सभी प्राथमिक शालाओं में शिक्षक और मिडिल स्कूल में भी शिक्षक होंगे। प्राथमिक और माध्यमिक शाला के बच्चों को शिक्षक मिलने से उनके शिक्षा की नींव मजबूत होगी। इसके बाद हाई और हायर सेकण्डरी विद्यालयों में भी गणित, रसायन, भौतकी, जीवविज्ञान, अंग्रेजी आदि विषय के व्याख्याता पदस्थ हो जाने से उन्हें कठिन लगने वाले विषय को अध्ययन करने में आसानी होगी। वे भी दसवीं पास करने के बाद गणित, साइंस लेकर पढ़ाई करने और बेहतर भविष्य बनाने में रूचि लेंगे। विषय शिक्षको के माध्यम से वे कठिन लगने वाले विषयों पर हो रही दुविधाओं, समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। विद्यालय में एक अलग शैक्षणिक वातावरण विकसित होगा।

मोटापे से निपटने फिट इंडिया और स्वस्थ जीवनशैली जरूरी

- छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की मोटापे के विरूद्ध मुहिम
- पोस्टर के माध्यम से स्कूली छात्राओं को किया जाएगा मोटापे के प्रति जागरूक
- खराब खान-पान और गतिहीन जीवनशैली के कारण बच्चों में बढ़ रहा है मोटापा

> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत में मोटापे की समस्या से निपटने के लिए मुहिम प्रारंभ कर दी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी 28 जनवरी 2025 को देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल के शुभारंभ समारोह के दौरान मोटापे से निजात पाने के लिए फिट इंडिया एवं स्वास्थ्य जीवनशैली अभियान के लिए देशवासियों से आव्हान की थी।

इस अभियान के तहत् देश में मोटापा जैसी समस्या से निपटने के लिए अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत् स्कूली बच्चों को पोस्टर के माध्यम से फास्ट फूड एवं मीठे पेय पदार्थों के कारण होने वाले मोटापे की समस्या के प्रति जारगरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में मोटापे की समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आव्हान फिट इंडिया एवं स्वस्थ जीवनशैली के लिए अभियान शुरू कर दी है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान दौर में मोटापा एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है, जो वयस्कों और बच्चों दोनों को प्रभावित कर रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक पांच में से एक वयस्क अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त है। द लैंसेट जीबीडी 2021 मोटापा पूर्वानुमान अध्ययन (2025) के अनुसार, भारत 2050 तक मोटापे के बोझ के मामले में विश्व का दूसरा सबसे प्रभावित देश बन सकता है, जहां मोटे वयस्कों की संख्या 2021 के 18 करोड़ से बढ़कर 44.9 करोड़ हो सकती है। मोटापा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और कुछ कैंसर जैसे गैर-संचारी रोगों के जोखिम को बढ़ाता है। यह मानसिक स्वास्थ्य, गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। साथ ही, यह स्वास्थ्य देखभाल लागत और उत्पादकता हानि के माध्यम से आर्थिक बोझ बढ़ाता है।

मोटापा आनुवंशिकी, अस्वास्थ्यकर आहार और कम शारीरिक गतिविधियों का परिणाम है। वैश्विक खाद्य बाजारों के एकीकरण ने प्रसंस्कृत और उच्च वसा, नमक, चीनी वाले खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाई है, जिससे प्रति व्यक्ति कैलोरी सेवन में वृद्धि हुई

है। बच्चों में मोटापा खराब खान-पान और गतिहीन जीवनशैली के कारण बढ़ रहा है। यह शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ बच्चों के आत्म-सम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और स्कूल प्रदर्शन को भी प्रभावित करता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोटापे और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए कई पहल शुरू की हैं। 10 मई 2025 को जारी दिशानिर्देशों के तहत कार्यस्थलों, स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों में ऑयल और शुगर बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। इन बोर्डों पर खाद्य पदार्थों में छिपी वसा और चीनी की मात्रा की जानकारी प्रदर्शित की जाती है, ताकि लोग संतुलित आहार चुन सकें।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों को ऑयल बोर्ड और शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है, ताकि छात्रों को अत्यधिक तेल और चीनी के सेवन के जोखिमों के बारे में जागरूक किया जा सके। स्कूलों से स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराने और शारीरिक गतिविधियों जैसे सीढ़ी चढ़ने, लघु व्यायाम तथा पैदल मार्गों को प्रोत्साहित करने का भी अनुरोध किया गया है।

सरकार ने पोषण अभियान और ईट राइट इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से पौष्टिक आहार और मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा को बढ़ावा दिया है। ये फसलें पोषक तत्वों से भरपूर, ग्लूटेन-मुक्त और मोटापा, मधुमेह, और हृदय रोग की रोकथाम में सहायक हैं। नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत, स्कूलों में स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। आयुष्मान भारत के स्कूल हेल्थ ऐंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत, शिक्षकों को हेल्थ ऐंड वेलनेस एंबेसडर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो बच्चों को स्वस्थ आदतें सिखाते हैं।

सीबीएसई और स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों और कार्यस्थलों में जागरूकता सेमिनार और कार्यशालाओं के आयोजन पर जोर दिया है। इनका उद्देश्य छात्रों और कर्मचारियों को संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के महत्व के बारे में शिक्षित करना, उच्च वसा, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के जोखिमों की जानकारी देना, और अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देना है, जैसे छात्रों द्वारा ऑयल और शुगर बोर्ड डिजाइन करना। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने अपने यूटयूब चौनल पर जागरूकता सामग्री और पोस्टर उपलब्ध कराए हैं, जिनका उपयोग स्कूल और कार्यस्थल कर सकते हैं।

भारत में मोटापे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सरकार, स्कूलों, और समुदायों का सामूहिक प्रयास आवश्यक है। फिट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, और ईट राइट इंडिया जैसी पहलें स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्कूलों में ऑयल और शुगर बोर्ड और जागरूकता सेमिनार बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देकर, भारत एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र की ओर अग्रसर हो सकता है। सभी नागरिकों से अपील है कि वे इन पहलों में सक्रिय रूप से भाग लें और स्वस्थ भारत के दृष्टिकोण को साकार करें।

एडवेंचर, अध्यात्म का अद्भुत संगम कोरबा के अनछुए पर्यटन रत्न

अगर आपका गोवा जाने का प्लान है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है. छत्तीसगढ़ में रहकर ही मिनी गोवा का एहसास कर सकते हैं. कोरबा शहर से करीब 45 किमी की दूरी पर स्थित सतरेंगा पिकनिक स्पॉट आपको गोवा वाली मस्ती और सुकून देता है. हसदेव-बांगो बांध के एक छोर पर सतरेंगा गांव है. यहां पहाड़ों और सुंदर वादियों के बीच बसा है सतरेंगा पिकनिक स्पॉट. यहां के मनमोहक नजारों का लुत्फ उठाने छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी पर्यटक आते हैं.

सतरेंगा में एक पहाड़ प्राकृतिक तौर पर शिवलिंग का आकार लिए हुए है, इसलिए इसे महादेव पहाड़ कहते हैं. ये पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे चर्चित पिकनिक स्पॉट में से एक गिना जाता है. यहां का पानी और माहौल आपको गोवा जैसा एहसास कराता है. दरअसल जंगल के बीच बांगो बांध का निर्माण छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी पर किया गया है. यहां पहाड़ों से घिरे बांध में बीच में कई छोटे-छोटे द्वीप है, जो इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं. उसी छोटे द्वीप में से एक सतरेंगा भी है. सतरेंगा कोरबा की नई पहचान बन चुका है.

छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला न केवल देश के ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, बल्कि अपने समृद्ध प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहरों और धार्मिक स्थलों के कारण एक उभरता हुआ पर्यटन केंद्र भी है। यहाँ देवपहरी जैसे सुरम्य झरनों से लेकर कुदुरमाल और कनकी जैसे ऐतिहासिक-धार्मिक स्थलों तक अनेक अद्वितीय अनुभव मिलते है।

प्रदेश सरकार द्वारा हाल के वर्षों में पर्यटन विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे कि होम स्टे की सुविधा और टूर गाइड की व्यवस्था भी की गई है। कोरबा के पर्यटन स्थलों की पहचान देश-विदेश के यात्रियों को भी आकर्षित कर रही है जिससे जिले को एक नई पहचान मिली है।

चौतुरगढ़ से सतरेंगा तक किलों की वीरगाथा

जलाशयों का सौंदर्य और आस्था के केन्द्रों से सज्जित कोरबा की अविस्मरणीय यात्रा के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि अब यह एक तेजी से उभरता पर्यटन केंद्र भी वन रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक आस्था के अद्भुत मेल ने इसे देश और विदेश के पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है।

निकटतम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन

प्रकृति के बीच ही रहकर यहां आप अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता सकते हैं. कोरबा जिले के सतरेंगा जाने के लिए हवाई सफर, ट्रेन और निजी वाहनों से पहुंचा जा सकता है. रेल मार्ग से जाने के लिए सबसे निकटतम स्टेशन कोरबा है. जिसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर है. बिलासपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 130 किलोमीटर है. हवाई मार्ग से जाने के लिए रायपुर एयरपोर्ट से लगभग 200 किलोमीटर और बिलासपुर एयरपोर्ट से 130 किलोमीटर दूर है. वहीं सतरेंगा पहुंचने के लिए कोरबा शहर से 45 किलोमीटर लंबी सड़क से आसानी से पहुंच सकते हैं.

सतरेंगा को पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप

छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग ने इसे वॉटर टूरिज्म के लिहाज से डेवलप किया है. इस अनोखी जगह को वॉटर स्पोर्ट्स और शानदार बनाता है. नीले पानी के बीच कई छोटे-बड़े टापू बने हैं. वहां तक बोट के जरिए पहुंचा जा सकता है. सतरंगी छटा बिखेरे हुए सतरेंगा को पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी. पिकनिक, वॉटर स्पोर्ट्स, कैंपिंग के अलावा यहां ठहरने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग ने शानदार रेस्ट हाउस बनाए हैं. ये रेस्ट हाउस बाहर से जितने खूबसूरत दिखते हैं अंदर से उतने ही आलीशान हैं. खाने-पीने के लिए भी यहां कैंटीन की अच्छी व्यवस्था है.

छत्तीसगढ़ में व्यापार और वाणिज्य को मिलेगी नई गति

• माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 पारित

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारित माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को कानूनी राहत, कारोबारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, कर मामलों का शीघ्र निराकरण और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है।

विधेयक में इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रावधानों को और स्पष्ट किया गया है ताकि कारोबार, कर भुगतान और क्रेडिट के उपयोग में पारदर्शिता आ सके। विशेष श्रेणी के लेन-देन (जैसे सेज, निर्यात, वेयरहाउस परिसंचरण) को स्पष्ट परिभाषित किया गया है। साथ ही वित्त अधिनियम, 2025 के केंद्र सरकार के संशोधनों के अनुरूप कई तकनीकी और प्रक्रियागत बदलाव किए गए हैं।

माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 के अनुसार इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नियम में संशोधन किया गया है। अब आईजीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत प्राप्त इनपूट टैक्स क्रेडिट का वितरण अपनी शाखाओं में करने की अनुमति मिलेगी। इससे जीएसटी अधिनियम की विसंगतियां दूर होंगी और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा मिलेगा।

विधेयक में ऐसे पेनाल्टी की राशि जिसमें टैक्स डिमांड शामिल नहीं है ऐसे प्रकरणों में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए पूर्व डिपोजिट 25 प्रतिशत राशि को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार वाउचर टैक्स निर्धारण को और अधिक स्पष्ट किया गया है। पहले जीएसटी प्रणाली में वाउचर पर कर निर्धारण के संबंध स्थिति स्पष्ट नही थी इस पर जीएसटी कब लगेगा इन्हें जारी करने के समय या इन्हें रिडीम करते समय इस संबंध में विभिन्न एंडवास रूलिंग अथारिटी मत भिन्नता थी। संशोधन विधेयक के अनुसार अब वाउचर रिडीम करते समय जीएसटी लगेगा।

तंबाकू आदि उत्पादों के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म लागू किया गया है, जिससे उनकी आपूर्ति श्रृंखला की कड़ी निगरानी हो सकेगी। ऐसे उत्पादों के सभी यूनिट पैकेट में एक क्यूआर कोड अंकित करना होगा, जिसे स्कैन करने पर निर्माता, उत्पाद, एमआरपी, विक्रेता, बिल आदेश, भुगतान के सभी रिकार्ड आदि जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही निर्माता और होलसेलर को इन यूनिट पैकेट के मूव्हमेंट का रिकार्ड रखना होगा। ताकि जांच एजेंसियों को किसी भी समय ऐसी सूचनाएं उपलब्ध हो सके।

विशेष आर्थिक क्षेत्र को प्रोत्साहन के तहत इन विशेष क्षेत्रों के वेयर हाउस में रखे गए वस्तुओं के निर्यात किए जाने से पूर्व वस्तुओं के फिजिकल मूवमेंट के बिना क्रय विक्रय किए जाने पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। यह बदलाव सेज में निवेश और कारोबार को बढ़ावा देगा तथा ये क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। विधेयक में 'प्लांट या मशीनरी' शब्दों के स्थान पर 'प्लांट और मशीनरी' शब्दो को प्रतिस्थापित किया गया है। प्लांट शब्द में 'भवन' सम्मिलित नहीं होगा एवं इस पर इनपुट क्रेडिट की पात्रता नहीं होगी। डिजिटल मुहर, डिजिटल चिन्ह या किसी प्रकार का अन्य चिन्हांकन सहित 'विशिष्ट पहचान चिह्नांकन' का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

छत्तीसगढ़ की उपलब्धियां

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 में राज्य को 16,299 करोड़ रूपए जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38 प्रतिशत है। इस वर्ष 18 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गई और छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर रहा। राज्य के भीतर माल परिवहन के लिए ई-वे बिल की सीमा 50,000 रूपए से बढ़ाकर 1,00,000 रूपए कर दी गई है, जिससे 26 प्रतिशत छोटे व्यापारियों को कागजी कार्यवाही से राहत मिली है।

नई सरकार के गठन के बाद से 43,612 नए पंजीकरण किए गए हैं। पंजीकरण प्रक्रिया को 13 दिनों से घटाकर अब सिर्फ 2 दिन में पूर्ण किया जा रहा है। पूर्व में केवल 15 जिलों में जीएसटी कार्यालय थे, अब राज्य के 33 जिलों में कार्यालय स्थापित कर दिये गये हैं। कर अपवंचन की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया गया है।

◦ बीजेपी विधायक भावना बोहरा की 151 किमी की कांवड़ यात्रा

नदी-जंगल और कठिन रास्ते तय कर भोरमदेव मंदिर में किया जलाभिषेक

"पंडरिया विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में 151 किमी की कांवड़ यात्रा निकली गई. भारी बारिश और कठिन रास्तों के बावजूद उन्होंने अपने 300 से अधिक कांवड़ यात्रियों के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक किया और छत्तीसगढ़ की समृद्धि और प्रदेशवासियों की सुख-शांति के लिए प्रार्थना की।"

पंडरिया नगर में दिखा जनसैलाब, हुआ भगवामय वातावरण

डोंगरिया महादेव में जलाभिषेक के बाद जब यात्रा पंडरिया नगर पहुंची, तो वहां भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर-हर महादेव और बोल बम के नारों से नगर गूंज उठा। करीब 3000 से अधिक लोगों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। भाजपा पदाधिकारी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, विभिन्न हिन्दू संगठनों और स्थानीय निवासियों ने कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा में भाग लिया।

भावना बोहरा ने कहा-''यह केवल यात्रा नहीं, सनातन संस्कृति का प्रतीक है''

विधायक भावना बोहरा ने डोंगरिया महादेव में जल अर्पित करने के बाद कहा, ''यह यात्रा मेरे लिए सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के संरक्षण का संकल्प है। आज जिस तरह से पंडरिया में जनसमूह उमड़ा, उससे यह स्पष्ट है कि शिवभक्ति और आस्था आज भी पूरे बल पर जीवित है। विधायक बोहरा ने कहा कि यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि लोक आस्था, संस्कृति और सामाजिक चेतना का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों, संगठन के सदस्यों और शिवभक्तों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें, यही मेरी मंगलकामना है। विधायक बोहरा ने विश्वास जताया कि भोलेनाथ और मां नर्मदा के आशीर्वाद से यह यात्रा सफल होगी और छत्तीसगढ़ के जीवन में नई शांति और समृद्धि का संचार करेगी।

डॉ. रमन सिंह ने फोन पर दी शुभकामनाएं

इस पुण्य यात्रा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने फोन कर भावना बोहरा से बातचीत की और सभी कांवड़ियों को यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस आध्यात्मिक प्रयास को जनआस्था और सेवा का प्रतीक बताया।

ग्रामवासियों ने पुष्पवर्षा कर किया स्वागत

यात्रा के दौरान कांवड़ियों का खुड़िया चौक, दुल्लापुर, डोंगरिया, डिंडौरी, नवरंगपुर, राम्हेपुर और गौरकांपा में भव्य स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं, युवा मोर्चा, विभिन्न हिन्दू संगठनों और स्थानीय शिवभक्तों ने पुष्पवर्षा कर उत्साह से सभी का अभिनंदन किया।

दिखा अपार उत्साह

बारिश और कठिन रास्तों के बावजूद कांवड़ यात्रियों में कोई थकावट नहीं दिखी। सभी श्रद्धालु उत्साह, ऊर्जा और भक्ति भाव से ओतप्रोत नजर आए। यात्रा के दौरान बोले गए ''बोल बम'' और ''हर हर महादेव'' के नारों ने पूरे मार्ग को शिवमय बना दिया। यह पवित्र यात्रा डोंगरिया महादेव और भोरमदेव महादेव के जलाभिषेक के साथ संपन्न हुई।

भोरमदेव में कांवड़ियों का भव्य स्वागत, सीएम साय ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल

सावन मास के तीसरे सोमवार को छत्तीसगढ़ के प्राचीन, धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के तीर्थ स्थल बाबा भोरमदेव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा की गूंज उस समय चरम पर पहुँच गई जब मुख्यमंत्री साय ने हजारों कांवड़ियों और शिवभक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। इस शुभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव उपस्थित थे। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब मुख्यमंत्री स्वयं श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पुष्पवर्षा कर रहे हैं। पुष्पवर्षा के पश्चात् मुख्यमंत्री साय ने बाबा भोरमदेव मंदिर पहुंचकर मंत्रोच्चारण, विशेष पूजा-अर्चना और रुद्राभिषेक किया तथा प्रदेश की समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री साय ने मंदिर परिसर में उपस्थित कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं से भेंट कर उनका हालचाल जाना और पूरे आत्मीय भाव से अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन मास के तीसरे सोमवार को बाबा भोरमदेव की पावन धरती पर शिवभक्तों के साथ जुड़ना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और गर्व का विषय है। हजारों श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन हेतु यहां पहुंचे हैं-यह हमारी आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की जीवंत मिसाल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अमरकंटक से 151 किलोमीटर पदयात्रा कर भोरमदेव मंदिर में जलाभिषेक करने वाली पंडरिया विधायक भावना बोहरा को भगवा वस्त्र और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ से अमरकंटक जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मध्यप्रदेश के अनूपपुर में 5 एकड़ भूमि आबंटन की प्रक्रिया जारी है, जहाँ एक भव्य श्रद्धालु भवन का निर्माण प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हेलीकॉप्टर से की गई पुष्पवर्षा इस पुण्य अवसर की महत्ता को और भी अभूतपूर्व बना गई है।

पौराणिक परंपरा का गौरवः भक्ति से सराबोर हुआ बाबा भोरमदेव परिसर

सावन मास में भगवान शिव-देवों के देव-के जलाभिषेक की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कवर्धा से 18 किलोमीटर दूर ग्राम चौरा में स्थित 11वीं शताब्दी का यह भोरमदेव मंदिर ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। श्रावण मास में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, मुंगेली, बेमेतरा, खैरागढ़, राजनांदगांव सहित मध्यप्रदेश के अमरकंटक से हजारों श्रद्धालु पदयात्रा कर बाबा भोरमदेव, बूढ़ा महादेव और डोंगरिया के प्राचीन जलेश्वर शिवलिंग में जलाभिषेक करने आते हैं। श्रद्धालु माँ नर्मदा से जल भरकर नंगे पाँव और भगवा वस्त्रों में 150 किलोमीटर से अधिक की दुर्गम यात्रा कर "बोल बम" के जयघोष और भजनों के साथ भोरमदेव, जलेश्वर महादेव और पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर पहुँचते हैं।

युवाओं के सपनों को लगेंगे पर, बनेंगे 34 नए नालंदा परिसर

◦ दूरस्थ शहरों में भी खुलेंगी सेंट्रल लाइब्रेरी

◦ युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिलेगा अच्छा माहौल

◦ युवाओं के करियर निर्माण में अहम साबित होंगी सेंट्रल लाइब्रेरी

◦ नगरीय प्रशासन विभाग ने नालंदा परिसरों के लिए मंजूर किए हैं 237.58 करोड

छत्तीसगढ़ सरकार उच्च शिक्षा हासिल कर रहे तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के सपनों को पर देने 34 नए नालंदा परिसर बना रही है। ये नालंदा परिसर केवल रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ जैसे बड़े शहरों में ही नहीं बन रहे, बल्कि दूरस्थ वनांचलों के सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, चिरमिरी, कुनकुरी, जशपुर, बलरामपुर, पेंड्रा जैसे शहरों में भी बन रहे हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पिछले दो वर्षों में 33 नए नालंदा परिसरों के लिए राशि स्वीकृति की है। वहीं रायगढ़ में सीएसआर से 700 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी का काम प्रगति पर है। इसके लिए रायगढ़ नगर निगम और एनटीपीसी (National Thermal Power Corporation) के बीच 42 करोड़ 56 लाख रुपए का करार हुआ है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर होगा।

इन सेंट्रल लाइब्रेरीज-सह-रीडिंग जोन्स से प्रदेशभर के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छा माहौल मिलेगा। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी पुस्तकें भी मिलेंगी। प्रदेश के हर वर्ग के युवाओं के करियर निर्माण में ये लाइब्रेरीज काफी मददगार और अहम साबित होंगे। इन सर्वसुविधायुक्त, अत्याधुनिक लाइब्रेरीज में युवाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने पिछले दो वर्षों में 33 नालंदा परिसरों के लिए 237 करोड़ 57 लाख 95 हजार रुपए मंजूर किए हैं। विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 17 नगरीय निकायों में 18 नालंदा परिसरों के लिए 125 करोड़ 88 लाख रुपए स्वीकृति किए गए हैं। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में अलग-अलग शहरों में 15 नालंदा परिसरों के लिए 111 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

इनमें से 11 नालंदा परिसरों के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर संबंधित निर्माण एजेंसीज को कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। ये जल्द ही आकार लेना शुरू कर देंगे।

नगरीय प्रशासन विभाग ने 11 नालंदा परिसरों के लिए जारी किए 19.15 करोड़

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 11 नगरीय निकायों में नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में कुल 19 करोड़ 14 लाख 87 हजार रुपए इसी महीने जारी किए हैं। विभाग द्वारा दुर्ग, राजनांदगांव और अंबिकापुर नगर निगम को प्रत्येक को दो करोड़ 85 लाख 57 हजार रुपए की प्रथम किस्त जारी की गई है। वहीं बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, कांकेर और जांजगीर नगर पालिका तथा कुनकुरी नगर पंचायत को प्रत्येक को एक करोड़ दस लाख 37 हजार रुपए प्रथम किस्त के रूप में जारी किए गए हैं। नालंदा परिसर के निर्माण के लिए जशपुर नगर पालिका को दो करोड़ 85 लाख 57 हजार रुपए की पहली किस्त जारी की गई है।

दस शहरों में 500 सीटर और 22 में 250 सीटर लाइब्रेरी बनेंगी

राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के अनुकूल माहौल देने के लिए दस नगरीय निकायों में 500 सीटर और 22 शहरों में 250 सीटर लाइब्रेरी बनाए जाएंगे। दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर और भिलाई नगर निगम तथा जशपुर, लोरमी एवं गरियाबंद नगर पालिका में 500-500 सीटर नालंदा परिसरों का निर्माण किया जाएगा। वहीं धमतरी और चिरमिरी नगर निगम, कवर्धा, जांजगीर-नैला, बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, कांकेर, नारायणपुर, बलरामपुर, मुंगेली, खैरागढ़, सक्ती, पेंड्रा, सारंगढ़, सूरजपुर, बैकुंठपुर, दंतेवाड़ा एवं सुकमा नगर पालिका तथा कुनकुरी, बसना और अंबागढ़-चौकी नगर पंचायत में 250-250 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन बनाए जाएंगे।

रायपुर में अभी तीन लाइब्रेरी संचालित, दो और बनेंगे

राजधानी रायपुर में अभी तीन सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन संचालित हैं। इनमें एक हजार सीटर नालंदा परिसर-सह-ऑक्सी रीडिंग जोन, 800 सीटर तक्षशिला सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-स्मार्ट रीडिंग जोन और 500 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों में नालंदा परिसर में पढ़ाई करने वाले 400 युवाओं ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होकर न केवल अच्छी नौकरियां हासिल की हैं, बल्कि प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश भी प्राप्त किया है। रायपुर में जल्दी ही एक हजार सीटर और 500 सीटर नई लाइब्रेरी का काम प्रारंभ होगा। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इनके लिए क्रमशः 22 करोड़ 80 लाख रुपए और 11 करोड़ 28 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

नालंदा परिसर सिर्फ इमारत नहीं, युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की बुनियादः साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर के नालंदा परिसर की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के सपनों को उड़ान देने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिले, इसके लिए हम अलग-अलग क्षेत्र के शहरों में नालंदा परिसरों का निर्माण कर रहे हैं। सुकमा से लेकर सूरजपुर और रायगढ़ से लेकर कवर्धा तक-हर कोने में अत्याधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन खोले जा रहे हैं। ये नालंदा परिसर सिर्फ इमारत नहीं, युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की बुनियाद हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने सभी सुविधाएं मुहैया कराने प्रतिबद्ध रू साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेशभर में नालंदा परिसरों के विस्तार के बारे में कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वसुविधायुक्त ये लाइब्रेरियां उच्च शिक्षा हासिल कर रहे तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को पढ़ाई का अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के साथ ही उत्ष्ट अध्ययन सामग्री भी प्रदान करेंगी। राज्य के युवाओं की मेहनत को उनके इच्छित मुकाम तक पहुंचाने में नालंदा परिसर बड़ी भूमिका निभाएंगे। यहां वे पूरे फोकस, लगन और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

◦ जरीन खान का ट्रोलर्स को करारा जवाब

क्या शादी करने से फिर से जवान हो जाऊंगी ?

बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को करारा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला जवाब दिया है. दरअसल, एक यूजर ने उनकी उम्र को लेकर तंज कसते हुए कमेंट किया था, 'शादी कर लो, बूढ़ी हो रही हो.' इस पर जरीन ने न सिर्फ स्पष्ट प्रतिक्रिया दी, बल्कि समाज में व्याप्त इस मानसिकता पर भी सवाल खड़े किए.

जरीन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो साझा किया और साथ ही कैप्शन में लिखा, 'हाय, मैंने अपने कुछ वीडियो और पोस्ट्स पर कमेंट्स पढ़े. उनमें से एक था, 'शादी कर लो, बूढ़ी हो रही हो.' तो मैं आप सभी से यह पूछना चाहती हूं, क्या शादी करने से मैं फिर से जवान हो जाऊंगी? इसका आखिर मतलब क्या है?'

जरीन यही नहीं रुकीं. उन्होंने आगे लिखा, 'क्या यह सिर्फ हमारे देश की सोच है या पूरी दुनिया की, कि जब किसी की जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, तो उसका हल शादी समझ लिया जाता है? अगर कोई इंसान खुद को संभालने की स्थिति में नहीं है, तो उस पर किसी और की जिम्मेदारी डालना क्या सही है?'

शादी कोई जादू की छड़ी नहीं

उन्होंने कहा, 'शादी कोई जादू की छड़ी नहीं है, जो किसी को तुरंत 'सुधार' देगी. आजकल तो शादी दो-तीन महीने भी टिक नहीं रही है. ऐसे में यह मान लेना कि शादी हर समस्या का हल है, यह सोच ही गलत है.' पोस्ट के अंत में जरीन ने बड़ी बेबाकी से लिखा, 'अब यह शादी का लड्डू नहीं, शादी का लॉलीपॉप बन गया है. जो देखता है, चूसने को तैयार बैठा है. आप क्या सोचते हैं?' जरीन की यह प्रतिक्रिया न सिर्फ उनके ट्रोलर्स को जवाब देती है, बल्कि एक बड़ी सामाजिक मानसिकता पर भी प्रहार करती है. यह बयान आज के युवाओं, खासकर महिलाओं के लिए एक सशक्त संदेश है कि शादी कोई सामाजिक दबाव नहीं, बल्कि व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए.

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY

Chhattisgarh, Bilaspur | AN AISECT GROUP UNIVERSITY

Approved by : PCI | AICTE | NCTE | BCI | Member of : AIU | Recognized by : UGC | A NAAC Accredited University

(Accredited "A Grade" by NAAC)

ACCREDITED WITH GRADE A NAAC

15th August

" Our freedom is a legacy, a gift from those who fought for it. Let's honor them by living lives worthy of their sacrifice"

HAPPY Independence DAY

BE THE CHANGE

Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.) Ph: +91-7753-253801, 6261-900581/82
E-mail: info@cvru.ac.in | admissions@cvru.ac.in

www.cvru.ac.in Follow us on:

City Office: Dr. C.V. Raman University, Infront of Pallav Bhavan, Ring Road No.2, Bilaspur (C.G.) Ph. 07752-448799, Mo. 9109028878

AdPRAYAS

CSPDCL
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

सस्ती नहीं मुफ्त बिजली की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

31 लाख परिवारों को मिल रहा हाफ बिजली बिल योजना का लाभ

15 लाख BPL परिवारों को 30 यूनिट फ्री + हाफ बिजली बिल योजना का लाभ

डबल सब्सिडी केंद्र के साथ मिल रही राज्य की भी सब्सिडी

हर महीने 200-360 यूनिट तक बिजली उत्पादन

बिजली बिल होगा शून्य बची बिजली से होगी कमाई

उपभोक्ता से बनें ऊर्जादाता

पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना

मासिक बिजली बिल से भी कम ई.एम.आई. में लगाएं रूफ टॉप सोलर प्लांट

सोलर प्लांट क्षमता	केंद्र सरकार की सब्सिडी	राज्य सरकार की सब्सिडी	कुल सहायता राशि	आसान मासिक EMI
1 kW	₹30,000	₹15,000	₹45,000	₹167
2 kW	₹60,000	₹30,000	₹90,000	₹333
3 kW	₹78,000	₹30,000	₹1,08,000	₹800

*बैंक द्वारा 6% ब्याज दर पर आसान किश्तों में 10 वर्षों के लिए ऋण सुविधा (ई.एम.आई.) उपलब्ध

हमारा संकल्प

हाफ बिजली से मुफ्त बिजली

QR कोड स्कैन करें

आवेदन प्रक्रिया व अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर जाएं

https://pmsuryaghar.gov.in/

RO No: 13385/43